सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

वर्ष- 17 अंक - 231 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरुवार 04 जून 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन, 76 की आयु में ली अंतिम सांस

मुंबई। फिल्म निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें लिवर से जुड़ी समस्याएं थीं। पहलाज के करीबी ने जानकारी दी कि उन्हें बीती रात अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज सुबह उनका निधन हुआ। वो लीवर से जुड़ी समस्या से जूझ रहे थे। निहलानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी-मानी हस्ती थे। वह देश की फिल्म सर्टिफिकेशन संस्था के पूर्व प्रमुख रहे हैं। वह कई बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता रहे हैं। इन फिल्मों में 'आंखें', 'अंदाज', 'तलाश', 'रंगीला राजा' और 'जूली 2' शामिल हैं। एक निर्माता के तौर पर, निहलानी अलग-अलग शैलियों की कई व्यावसायिक हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे। फिल्म उद्योग में उनका योगदान कई दशकों तक फैला रहा।

जुलाई में होगी 10वीं-12वीं की पूरक परीक्षा, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी की डेटशीट

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने वर्ष 2026 के लिए 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार, मुख्य परीक्षा में असफल रहे या अपने अंकों में सुधार करना चाहने वाले विद्यार्थियों को एक और अवसर मिलेगा। पूरक परीक्षा को द्वितीय मुख्य एवं अवसर परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। सभी परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी और परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। हायर सेकेंडरी (कक्षा 12) की पूरक परीक्षाएं 8 जुलाई 2026 से शुरू होकर 22 जुलाई 2026 तक चलेंगी। परीक्षा का पहला पेपर हिंदी विषय का होगा। इसके बाद विभिन्न विषयों की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार हाई स्कूल (कक्षा 10) की पूरक परीक्षाएं 9 जुलाई से प्रारंभ होकर 21 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएंगी। परीक्षा की शुरुआत गणित विषय से होगी।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य

रायपुर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जनता को यह आश्वासन देना चाहता है कि आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों, जिसमें पेट्रोल (मोटर स्पिरिट), डीजल (हाई-स्पीड डीजल) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) शामिल हैं, की उपलब्धता पूरे राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात IOCL, BPCL और HPCL के सभी आपूर्ति चैनलों के माध्यम से पूरी तरह से सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। आपूर्ति की समग्र स्थिति बेहद स्थिर और पर्याप्त है, जिसने पिछले महीने के दौरान देखी गई मांग में बढ़ोतरी को सफलतापूर्वक संभाल लिया है। मुख्य आपूर्ति टर्मिनलों और भंडारण डिपो से लेकर स्थानीय खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पंपों) तक फैली पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला कुशलतापूर्वक और बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है।

सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम रहने का रिकार्ड बनाएंगे मोदी, 10 जून को बनेगा एक नया कीर्तिमान

नईदिल्ली ए.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे।

आंकड़ों के अनुसार आजादी के बाद देश के पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

पंडित नेहरू 27 मई 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। यह अवधि कुल 4,398 दिनों की रही। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक उनका लगातार कार्यकाल 4,399 दिनों का हो जाएगा, जो नेहरू के रिकॉर्ड से एक दिन अधिक होगा। सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के मामले में तीसरे पायदान पर काबिज इंदिरा गांधी का 4,077 दिनों का लगातार कार्यकाल मोदी 25 जुलाई 2025 को ही पार कर चुके हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4,077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहीं, जो लगभग 11 वर्ष और दो महीने की अवधि थी।

अलग-अलग दौर, चुनौतियां भी अलग

कार्यकाल की तुलना करें तो दोनों नेताओं ने भारत का नेतृत्व बिल्कुल अलग परिस्थितियों में किया। नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद नवगठित भारत का नेतृत्व संभाला, जबकि मोदी ने अधिक आबादी, जटिल अर्थव्यवस्था, बहुदलीय राजनीति और डिजिटल निगरानी वाले भारत का नेतृत्व किया। नेहरू के समय देश की आबादी लगभग 34 करोड़ थी, जबकि मोदी के पीएम बनने तक यह 131 करोड़ से अधिक हो चुकी थी और अब 146 करोड़ के पार है। मोदी ने सोशल मीडिया और 24 घंटे की सार्वजनिक निगरानी के दौर में नेतृत्व किया है, जहां सरकार के हर फैसले का तत्काल मूल्यांकन होता है।

छत्तीसगढ़ में बासमती धान मिशन की तैयारी पायलट प्रोजेक्ट पर होगा काम, बनी सहमति

- **इंडियन राईस एक्सपोर्ट फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कृषिमंत्री नेताम के साथ की बैठक**

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बासमती धान की खेती के विस्तार पर राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। कृषि विकास मंत्री राम विचार नेताम की अध्यक्षता में अटल नगर, नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि संचालक राहुल देव, अनुसंधान संचालक डॉ संजय त्रिपाठी, बीज निगम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक तथा इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा देने व

बैठक में कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ बासमती धान की खेती को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में गंभीरता और तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। श्री नेताम ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, सरकार उन्हें प्राथमिकता के साथ लागू करेगी। सामान्य धान की खेती के फसल विविधिकरण तथा राज्य में बासमती का रकबा बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रदेश का तापमान बासमती के लिए उपयुक्त

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त परदेशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बासमती धान की खेती को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य में धान की विभिन्न किस्मों का व्यापक उत्पादन होता है, लेकिन बासमती एवं अन्य सुगंधित चावलों की अंतरराष्ट्रीय और यूरोपीय बाजारों में विशेष मांग है तथा इनके बेहतर दाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां की जलवायु और तापमान बासमती उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। चयनित क्षेत्रों में बासमती धान का रकबा बढ़ाकर किसानों को अधिक लाभ दिलाने की योजना बनाई जाएगी।

आईआरएफ ने दिया सहयोग का भरोसा

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने राज्य में बासमती धान के उत्पादन के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। फेडरेशन ने किसानों के लिए बायबैक व्यवस्था, विपणन सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुगंधित चावल के निर्यात को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि उत्पादन से लेकर विपणन और निर्यात तक एक समन्वित व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और छत्तीसगढ़ सुगंधित चावल उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बना सके।

सुशासन तिहार में गायब रहने पर भड़के सांसद बृजमोहन अग्रवाल

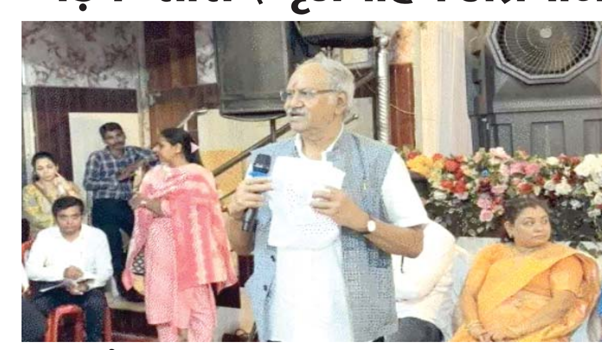

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जिले के गोबरा नवापारा में आयोजित सुशासन 'तिहार शिविर' में शिकायत मिलने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेंजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेंजर यहां क्यों नहीं है, शोकॉज नोटिस जारी करो और उसे सस्पेंड करो।

मामला कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में वन विभाग की आपत्ति और रेंजर की गैरमौजूदगी से जुड़ा था। शिविर के दौरान जब यह मामला सामने आया तो सांसद ने नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि जब शिविर में जनता की समस्याएं सुनने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहना है, जिम्मेदार अधिकारी का अनुपस्थित रहना लापरवाही है। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को संबंधित रेंजर के खिलाफ सस्पेंशन के निर्देश दिए। शिविर में अलग-अलग विभागों से जुड़े आवेदन भी सामने आए। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिविर में मिले आवेदनों का निराकरण 7 दिनों के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि तय समय में काम पूरा नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निजी अस्पताल में भीषण आग, पांच की मौत, 20 घायल

मुजफ्फरपुर ए.। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में गुरुवार तड़के करीब दो बजे आग लग गई। अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में औराई के 30 वर्षीय शशांक कुमार, कथैया की गीता देवी और तरियानी-शिवहर के 57 वर्षीय उदय कुमार, कृष्ण नंदन और चंचला कुमारी के शव की पहचान हो सकी है। करीब 20 लोगों के हताहत होने की जानकारी आई, लेकिन मौतों की संख्या पर औपचारिक पुष्टि नहीं हो रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल की ऊपरी मंजिल स्थित आईसीयू

में लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया और मरीजों व उनके परिजनों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया गया।

ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में इस घटना से अफरातफरी मच गई। मौके पर कई घंटे बाद भी लोग मौतों की वास्तविक संख्या नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि बेसुध अवस्था में निकाले गए लोगों को आसपास के दूसरे अस्पतालों में ले जाने की बात कही जा रही थी। बचाव कार्य में अस्पताल के कर्मी शुरू में लगे थे, लेकिन फिर अफरातफरी की स्थिति हो गई। ब्रह्मपुरा थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि आग की सूचना शोरगुल से ही मिली थी। इसके बाद जिसे-जैसे मौका मिला, भागते हुए बचाव कार्य में लग गए हैं। दमकलकर्मियों ने शॉर्ट सर्किट से आग और 10 से 15 बेसुध लोगों को निकाले जाने की बात कही।

बड़ी कार्रवाई, दो दिन में हत्थे चढ़े 501 बांग्लादेशी नागरिक

अहमदाबाद। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने गुरुवार को राज्य भर में घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन डेल्टा हंट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य भर में 501 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि यह आंकड़ा देर रात तक और बढ़ सकता है।

इस कार्रवाई को लेकर क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि

अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के चांडोला, गुलाबनगर और खोदियारनगर सहित कई इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्होंने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस अभियान के दौरान इन प्रवासियों के बारे में सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने पाया है कि कई घुसपैठियों के पास आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जो उन्होंने धोखाधड़ी के जरिए हासिल किए थे। इसके चलते दस्तावेज जालसाजी नेटवर्क और भारत में उनके रहने को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों की व्यापक जांच शुरू की गई है।

रायपुर के बढ़ईपारा में आग : किराना दुकान से उठीं आग की लपटें, समय रहते टला बड़ा हादसा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। के बढ़ईपारा क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किराना दुकान में अचानक आग भड़क उठी। दुकान से उठते धुएं और आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय दुकान बंद थी। इसी दौरान लोगों ने दुकान के भीतर से धुआं निकलते देखा। कुछ ही देर में आग ने दुकान के अंदर रखे सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग बढ़ती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों की तत्परता के चलते आग को आसपास की अन्य दुकानों और मकानों तक फैलने से रोक लिया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया।

दूरस्थ गांवों में बीएसएनएल के 4जी टॉवरों का भौतिक सत्यापन

कवर्धा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अब तक किसी भी प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी, वहां अब भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के माध्यम से आधुनिक संचार सुविधाएं पहुंचने लगी हैं।

परियोजना के अंतर्गत दूरस्थ इलाकों में 4जी मोबाइल टॉवर स्थापित करने की जिम्मेदारी भारत संचार

निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपी गई है। इसी क्रम में कबीरधाम (कवर्धा) जिले के ग्राम मुड़वाही, झलमला तथा घुघवा डहरा में स्थापित 4जी मोबाइल टॉवरों का भौतिक सत्यापन नोडल अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी टोपेश कुमार साहू द्वारा किया गया। सत्यापन के दौरान उन्होंने संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर टॉवरों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया तथा स्थानीय ग्रामीणों एवं हितग्राहियों से संवाद कर फीडबैक प्राप्त किया।

ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल नेटवर्क सुविधा शुरू होने के बाद उनके दैनिक जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब वे मोबाइल फोन के माध्यम से सहज संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग बढ़ा है तथा बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच मिल रही है। ग्रामीण अंचलों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा आधुनिक संचार सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में 4जी सैचुरेशन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है। यह योजना दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में संचार, शिक्षा, डिजिटल लेनदेन और सूचना पहुंच के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को मनोरंजन सहित विभिन्न डिजिटल सेवाओं का लाभ भी मिलने लगा है।

छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न : इन 21 जिलों में आज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत का दौर जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वातावरण में नमी बढ़ने से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की जा सकती है।

प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी राजनांदगांव में महसूस की गई, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा क्षेत्र में सबसे अधिक 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं कोरबा और पेंड्रा रोड में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा मैनपाट, कटघोरा, सूरजपुर, कांसाबेल और अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा दर्ज की गई।

मानसून केरलम पहुंचा

मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिन में मानसून पूरे गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है।

संपादकीय

खाक हुई जिंदगियां

आपराधिक लापरवाही की जवाबदेही हो तय

दिल्ली में मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद भले ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन सवाल है कि अग्निकांड में मरे लोगों का जीवन कौन लौटाएगा? आखिर देश की राजधानी में अकसर होने वाले अग्निकांडों का सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? क्या इस आपराधिक लापरवाही की जवाबदेही तय होगी? एक बार फिर अंधे लालच और आंख मूंदे तंत्र की लापरवाही से बुधवार को एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जतायी जा रही है। घटना ने एक बार फिर होटल, गेस्टहाउस और रेस्तरां संचालन की निगरानी करने वाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विडंबना देखिए कि मरने वालों में अधिकांश विदेशी लोग भी हैं, जो सस्ता इलाज कराने भारत आए थे। एक ही परिवार के आठ लोगों के अग्निकांड का शिकार होना बेहद दुखद है। विडंबना देखिए कि जिस एक मंजिला भवन को छह कमरों का गेस्ट हाउस चलाने की अनुमति मिली थी, वहां शासन-प्रशासन की नाक के नीचे एक छह मंजिला होटल बना दिया गया, जिसमें 26 कमरे और रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। जिसमें अस्सी से सौ लोगों की मौजूदगी बतायी जा रही है। निश्चित रूप से यह महज आग से जुड़ा हादसा नहीं है बल्कि होटल संचालन से जुड़े नियमों की अनदेखी, निगरानी करने वाले विभागों की लापरवाही और तंत्र की विफलता का परिचायक है। लेकिन गाहे-बगाहे होने वाले अग्निकांडों के बावजूद तंत्र की काहिली बदस्तूर जारी है। जांच के दायरे में घटना के बाद फरार होटल मालिक ही नहीं, बल्कि वे अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको संचालित करने के नियमों का अनुपालन नहीं किया और भवन निर्माण की स्वीकृति व उपयोग की अनुमति दी। यह जानते हुए भी कि होटल में निकासी का मार्ग बेहद संकरा है और अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं।

> “ विडंबना देखिए कि मरने वालों में अधिकांश विदेशी लोग भी हैं, जो सस्ता इलाज कराने भारत आए थे। एक ही परिवार के आठ लोगों के अग्निकांड का शिकार होना बेहद दुखद है। विडंबना देखिए कि जिस एक मंजिला भवन को छह कमरों का गेस्ट हाउस चलाने की अनुमति मिली थी, वहां शासन-प्रशासन की नाक के नीचे एक छह मंजिला होटल बना दिया गया, जिसमें 26 कमरे और रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। जिसमें अस्सी से सौ लोगों की मौजूदगी बतायी जा रही है।

दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के बारे में बताते हैं कि आपातकालीन निकासी के अभाव व सुरक्षा मानकों का पालन न होने से ज्यादा मौतें हुई। धुंआ निकलने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण भी ज्यादा लोग दम घुटने से मौत के मुंह में समा गए। आखिर प्रशासन के अधिकारियों ने यह क्यों नहीं देखा कि स्वीकृत क्षमता से चार गुना विस्तार कर लिया गया है। गेस्ट हाउस के निर्माण में तमाम लाइसेंस शर्तों का घोर उल्लंघन हुआ। आपातकालीन निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिये, बदहवासी में ऊपरी मंजिलों से कूदते नजर आए। होटल के बाहर फैले बिजली के तार और अग्निकांड में हुई व्यापक क्षति बताती है कि विद्युत सुरक्षा मानकों का भी पालन ठीक से नहीं हुआ। जाहिर बात है कि गेस्ट हाउस से होटल बनाने से, उपयोग में हुए बदलाव की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकाय की होती है। यदि वर्षों से यह अवैध रूप से संचालित था, तो जांच व कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि इसकी अग्नि सुरक्षा को लेकर एनओसी जारी की भी गई थी तो उसके बाद निरीक्षण व नियमों का अनुपालन क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया? जाहिर बात है कि लाइसेंस प्राप्त करने वाले होटलों व रेस्टोरेंट की नियमित जांच करके इनके मालिकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। क्यों किसी भी विभाग ने निरीक्षण व कार्रवाई की जहमत नहीं उठायी? क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारी ले-देकर खामोश होकर बैठ गए? विडंबना देखिए कि बेसमेंट में कमरे,किचन बना दिए गए, लेकिन वेंटिलेशन व इमरजेंसी एग्जिट का कोई प्रावधान नहीं था। जिससे होटल धुंआ निकासी की चिमनी बनकर रह गया और तमाम लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताते हैं कि आरोपी होटल मालिक आसपास में ही कुछ पार्टनरों के साथ मिलकर तीन होटल संचालित कर रहा था और सब ही जगह आपराधिक लापरवाही नजर आई। मोटे मुनाफे के लिये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन स्थानीय प्रशासन व जवाबदेह विभाग बेपरवाह बने रहे। निश्चय ही यह स्थिति सख्त कार्रवाई के बाद बदलनी चाहिए।

मध्य वर्ग का सफर : नीतियों से मिलती प्रगति, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के

भारत का सामाजिक-आर्थिक चेहरा बदल रहा है। इस बदलाव के केंद्र में आगे बढ़ता और आत्मविश्वास से लबरेज मध्य वर्ग है। इस तबके को एक समय में सतर्क खर्च और सीमित विकल्पों के लिए जाना जाता था। लेकिन आज मध्य वर्ग के परिवार ज्यादा सुरक्षा, अवसर और आकांक्षा की अनुभूति कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में कराधान, स्वास्थ्यसेवा, आवासन, डिजिटल सेवाओं, अवसंरचना, शिक्षा और उद्यमिता में सुधारों से रोजमर्रा का जीवन ज्यादा किफायती और सुविधाजनक हो गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, सेवाओं तक आसान पहुंच, किफायती आवास, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि और डिजिटल सशक्तीकरण से सुख-साधनों और आत्मविश्वास में इजाफा हुआ है। आय में वृद्धि और अवसरों के विस्तार के साथ भारत का मध्य वर्ग अब खुद को सिर्फ बदलाव के अनुरूप ढाल ही नहीं रहा बल्कि राष्ट्र के विकास, महत्वाकांक्षा और भविष्य की संपन्नता में सक्रिय योगदान कर रहा है।

एक समय भारत के मध्य वर्ग को उसके सतर्क खर्चों, सीमित विकल्पों और छोटी महत्वाकांक्षाओं से पहचाना जाता था। आज यह वास्तविकता बदल चुकी है। बढ़ती आय, डिजिटल पहुंच और फैलते अवसरों के साथ ही आकांक्षाएं उपलब्धियों में बदल रही हैं। भारतीय समाज का यह तबका सरकार के समर्थन से लगातार सशक्त हो रहा है। वर्ष 2014 से आयकर छूट सीमाओं में रिकॉर्ड वृद्धि से लेकर जीएसटी सुधारों तक से उसकी बचत और खर्च करने योग्य आय बढ़ी है। अब यह मध्य वर्ग ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सशक्त होकर भारत की विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है।

सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापक सुधारों के माध्यम से भारत के मध्य वर्ग का सशक्तीकरण किया है। सरल कराधान तथा ज्यादा मजबूत बैंकिंग, बीमा और पेंशन प्रणालियों से वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है। विस्तार लेते शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार से नए अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, सुगम स्वास्थ्यसेवा, सुदृढ़ शिक्षा और कौशल विकास तथा बेजोड़ डिजिटल शासन से रोजमर्रा की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। ये सभी कदम मिल कर संपत्ति सृजन और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं।

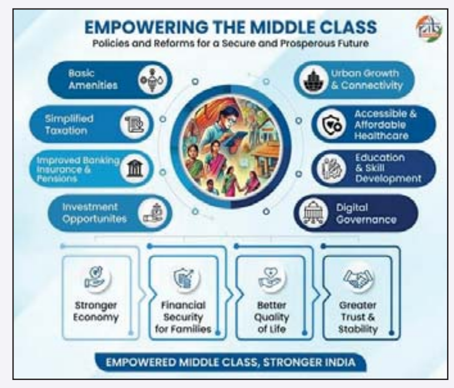

सरकार ने पिछले 12 वर्षों में भारतीय मध्य वर्ग की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया है। कराधान में कमी, बैंकिंग तक पहुंच में सुधार, व्यापक बीमा कवरेज और पेंशन के विस्तार से वित्तीय तनाव में कमी आई है। रियायती ब्याज दरों और डिजिटल सुधारों से बचत, ऋण और वित्तीय योजना निर्माण ज्यादा सुगम और सुविधाजनक हो गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, सेवाओं और कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण प्रदान करती है। यह योजना सशक्तिकरण का एक मज़बूत ज़रिया बन गई है, जिसके तहत मार्च 2026 तक 40.07 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 57 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत किया है, वित्तीय समावेशन को गहरा किया है और भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के निरंतर विकास को गति दी है। मध्यम वर्ग के लिए, पीएमएमवाई छोटे व्यवसायों को शुरू करने में मदद करती है, स्व-रोजगार में सहायता करती है और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को कम करके वित्तीय स्थिरता में सुधार लाती है।

पिछले 12 वर्षों में, सरकार ने पूरे भारत में शहरी अवसंरचना और कनेक्टिविटी का विस्तार किया है। बेहतर आवास, तेज़ परिवहन और आधुनिक सार्वजनिक अवसंरचना ने रोज़मर्रा के शहरी जीवन को बेहतर बनाया है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण और बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी ने मध्यम वर्ग के लिए यात्रा को ज़्यादा सुरक्षित, तेज़ और किफ़ायती बना दिया है।

शहरी (पीएमएवाई-यू)- आवास के लिए 2015 में शुरू की गई इस योजना ने करोड़ों लोगों को सुरक्षित आवास देकर उनकी ज़िंदगी बदल दी है। पीएमएवाई-यू 2.0 योजना इस काम को और आगे बढ़ाती है। इसे 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत (सितंबर 2024 से प्रभावी) शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ और पात्र लाभार्थियों को सहायता देना है। मध्यम वर्ग के लिए घर सुनिश्चित करने के लिए 8.76 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

रेलवे का विस्तार- पिछले 12 सालों में, भारत में ट्रेन से सफ़र करना ज़्यादा सुरक्षित, तेज़, पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक हो गया है। भारतीय रेलवे के लिए बजट में मिलने वाली मदद 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 2.78 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 'कवच' नाम के एक स्वदेशी सिस्टम से सुरक्षा में सुधार हुआ है; यह सिस्टम ऑटोमैटिक ब्रेकिंग के ज़रिए ट्रेनों की टक्कर को रोकता है। 130 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाली हाई-स्पीड रेल पटरियों का विस्तार 2014 के 5,036 किमी से बढ़कर 2026 में 23,713 किमी हो गया है। भारत ने जनवरी 2026 में अपनी भविष्योन्मुखी 'वंदे भारत' स्लीपर सेवा की भी शुरुआत की, जबकि अब देश भर में 60 'अमृत भारत' ट्रेनें चल रही हैं।

सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा

देश भर में लाखों परिवारों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में काफी विस्तार हुआ है। पिछले बारह वर्षों में दवाओं की कम कीमतें, व्यापक बीमा कवरेज और बेहतर उपचार सुविधाओं ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बोझ को कम किया है। निवारक देखभाल, रोग नियंत्रण और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना ने भी मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाया है।

2015 के बाद इस योजना में काफी बदलाव किए गए। इसका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों के ज़रिए काफी कम कीमतों पर, गुणवत्ता पूर्ण जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराना है। फिलहाल, 18,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र 50-80ल कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। औसतन, रोज़ाना लगभग 10 से 12 लाख लोग इन केंद्रों पर आते हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत के मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च में कमी आई है जिसका उन्हें का लाभ मिलता है। 2,110 दवाओं, 315 सर्जिकल उपकरणों आदि का उत्पाद इलाज को बेहतर बनाता है। पिछले 11 वर्षों में, जनऔषधि उत्पादों ने परिवारों के दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करके 40,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद की है।

सितंबर 2018 में शुरू की गई, यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना है। यह योजना सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करती है। इससे पूरे भारत के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल रहा है, जिसमें मध्यम-वर्गीय परिवार भी शामिल हैं; 70 वर्ष से अधिक आयु के 86.51 लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' दिए गए हैं।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहचान, बैंकिंग और कनेक्टिविटी के सोच-समझकर किए गए एकीकरण के ज़रिए विकसित हुआ। इसने 'जैम ट्रिनिटी' का रूप लिया, जन धन खाते, आधार और मोबाइल की व्यापक पहुँच संभव हुई। इन तीनों ने मिलकर भारत के डिजिटल बदलाव की नींव रखी, जिससे नागरिकों और सरकार के बीच सीधे और सत्यापित किए जा सकने वाले संपर्क स्थापित हो सके।

विकास का आधारः मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण

पिछले बारह वर्षों में, सरकार मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। इसकी नीतियों और सुधारों ने लाखों परिवारों के लिए रोज़मर्रा की चुनौतियों को आसान बनाया है। इन्होंने वित्तीय सुरक्षा, आवास की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के अवसरों को मज़बूत किया है। ये प्रयास भारत की विकास गाथा में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। निष्पक्षता और सुलभता को बढ़ावा देकर, सरकार ने मध्यम-आय वाले परिवारों के बीच अधिक विश्वास जगाया है। इस निरंतर दृष्टिकोण ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है और भविष्य की प्रगति के लिए एक मज़बूत नींव रखी है।

प्रकृति के बदलते मिजाज को लेकर गंभीरता जरूरी

ज्ञानेन्द्र रावत

महात्मा गांधी ने वर्ष 1928 में ही उत्पादन और खपत के पश्चिमी मॉडल के चलते वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय असंतुलन की चेतावनी देते हुए कहा था—'ईश्वर कभी नहीं चाहता कि भारत कभी पश्चिम की तरह औद्योगिकीकरण अपनाए।' साथ ही कहा था कि 'एक छोटे से द्वीप साम्राज्य (इंग्लैंड) के आर्थिक साम्राज्यवाद ने आज दुनिया को जंजीरों से जकड़ रखा है। यदि तीस करोड़ की आबादी वाले देश ने ऐसा आर्थिक शोषण किया तो पूरी दुनिया टिड्डियों की तरह बेकार हो जाएगी।'

गांधीजी का मानना था कि देश को आज़ादी के बाद गरीबी दूर करने और लोगों के सम्मानजनक जीवनयापन की दृष्टि से आर्थिक विकास करना ही होगा। ऐसे में भारत को अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में कहीं अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना होगा। दुखद है कि आज़ाद भारत की सरकारों ने गांधी के विचारों को पूरी तरह बिसरा दिया। परिणामस्वरूप, जहां मानव जीवन प्रभावित हुआ, वहीं संसाधनों पर कॉर्पोरेट घरानों के कब्जे से ग्रामीण और आदिवासी समाज बेदखली का शिकार हुआ। साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के कारण प्रदूषण की समस्या ने भयावह रूप ले लिया।

इस तबाही के विरोध में देश में चिपको, नर्मदा और मछुआरों के आंदोलन सामने आए। इसके उपरांत देश में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई और पारिस्थितिक नुकसान रोकने के लिए अनेक कानून

बने। लेकिन सत्ता पर काबिज विभिन्न सरकारों ने समाज के व्यापक हित के बजाय निजी कॉर्पोरेट घरानों के हितों को सर्वोपरि मानकर उनके आगे झुकना उचित समझा। कॉर्पोरेट घरानों के निजी स्वार्थ के चलते प्रदूषित शहर, भयावह स्तर तक प्रदूषित वातावरण, मरती जीवनदायी नदियां, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, गिरता भूजल स्तर, खत्म होते जलस्रोत व जंगल, प्रदूषित मिट्टी, बंजर होती जमीन आदि पर्यावरण विनाश और तबाही के स्पष्ट सबूत हैं। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके बावजूद यह सिलसिला बेरोकटोक जारी है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो बीस वर्ष पहले हम सालाना आठ अरब मीट्रिक टन कार्बन वायुमंडल में छोड़ रहे थे, जिसका आंकड़ा बढ़कर आज डेढ़ गुणा से भी अधिक हो गया। इसके कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा जोरों पर है। प्रकृति का मिजाज बदल रहा है, और इसमें जलवायु परिवर्तन ने अहम भूमिका निभाई है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि दुनिया में ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए कोयला, तेल और गैस का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। भारत के संदर्भ में ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन रोकने के भारत के प्रयास अभी भी नाकाफी हैं। भारत ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 33-35 प्रतिशत तक कमी लाने का ऐलान किया था, लेकिन पेरिस समझौते के मुताबिक डेढ़ डिग्री के लक्ष्य के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। देश को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने उत्सर्जन लक्ष्य नए सिरे से तय करने की आवश्यकता है, अन्यथा 2095 तक धरती का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।

यदि कार्बन उत्सर्जन में कमी न आई तो जल संकट बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, ध्रुवों की बर्फ तेज गति से पिघलेगी, समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। नतीजन, दुनिया के कई देश पानी में डूब सकते हैं। समुद्र किनारे बसे सैकड़ों शहर-महानगर जलमग्न होंगे, और लगभग 20 लाख से अधिक प्रजातियां सदा-सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। वहीं, सदियों से जीवन के आधार रहे खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। विशेष रूप से बी-1, बी-2, बी-5 और बी-8 जैसी विटामिनों में कमी आएगी। बीमारियों से बचाने वाले जैव रसायनों में भी कमी आने की संभावना है। यदि पृथ्वी का तापमान और अधिक बढ़ गया तो धरती का एक-चौथाई हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। वहीं 20-30 प्रतिशत हिस्सा सूखे का शिकार होगा। नतीजतन, दुनियाभर में लगभग 150 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे। जंगलों में आग की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत समेत दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण यूरोप, मध्य अमेरिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा।

चौंकाने वाली बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पहले बीते चार दशकों में कम हो चुकी उर्वरा शक्ति वाली जमीन की सेहत बिगड़ने की दर अब सौ गुणा बढ़ गई है। उस हालत में भविष्य में दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए अन्य संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। आने वाले 24 वर्षों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका को इस चुनौती का भीषण सामना करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में सदी के अंत तक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। इसका असर खाद्यान्न, पेयजल और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। नतीजन आम आदमी का जीवन मुहाल हो जाएगा।

प्रकृति के सारे उतार-चढ़ाव मानवता को संभलने के लिए चेतावनी हैं। पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम लोग इन्हें समझने और गंभीरता से लेने के बजाय नजरअंदाज कर रहे हैं। जरूरत इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करने की है मसलन, जीवनशैली में बदलाव व प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना। ताकि पूरी पृथ्वी और मानवता के साथ-साथ इस ग्रह पर रहने वाले तमाम जीव-जंतुओं को विनाश से बचाया जा सके।

- लेखक पर्यावरणविद् हैं।

पीएम स्वनिधि योजना : पथ विक्रेताओं के सशक्ति करण और वित्तीय समावेशन की यात्रा

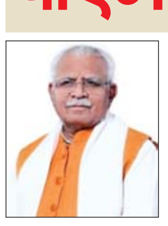

मनोहर लाल खट्टर

भारत में शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक देश की लगभग 50 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। वर्तमान में शहरी कार्यबल का लगभग 66ल हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा है, जो शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इस अनौपचारिक क्षेत्र में पथ विक्रेताओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फल, सब्ज़ियाँ, चाय, नाश्ता, कपड़े तथा दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने वाले ये लाखों विक्रेता न केवल करोड़ों नागरिकों के जीवन को सुगम बनाते हैं, बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करते हैं। इसके बावजूद, लंबे समय तक उनकी औपचारिक बैंकिंग और ऋण तक पहुँच सीमित रही। क्रेडिट हिस्ट्री के अभाव में उन्हें अक्सर ऊँची ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण लेना पड़ता था, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च हो जाता था।

भारतीय पथ विक्रेता बदलती वैश्विक परिस्थितियों और विभिन्न आर्थिक व्यवधानों के बीच भी अपनी दृढ़ता और संघर्षशीलता के लिए जाने जाते हैं। पीएम स्वनिधि ने उनकी इस उद्यमशीलता को नई ऊर्जा प्रदान की है। यह केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सम्मान, पहचान और नए अवसरों का एक सशक्त माध्यम बनी है। योजना की सफलता का प्रमुख आधार "Whole of Government Approach" रहा, जिसमें केंद्र, राज्य, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकिंग संस्थानों के समन्वित प्रयासों ने इसे देशभर अभूतपूर्व रूप से पहुँचाया तथा उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किये।

इस योजना के अंतर्गत लाखों विक्रेताओं के बैंक खाते सक्रिय हुए, उनका वित्तीय व्यवहार दर्ज होने लगा और पहली बार उनके लिए एक औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री का निर्माण हुआ। इससे भविष्य में और अधिक ऋण तथा वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच आसान हुई और वे आज बैंक के सम्मानित ग्राहक और उद्यमी के रूप में उभरे हैं। इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल सशक्तिकरण है। यूपीआई और क्यूआर-कोड आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इस पहल ने अभी तक 55 लाख विक्रेताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा, उनके लेन-देन को पारदर्शी बनाया और उनकी वित्तीय साख को मजबूत किया है।

योजना की सोच केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही। 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवारों को भारत सरकार की आठ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। अब तक 50 लाख से अधिक पथ विक्रेता परिवारों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत 1.52 करोड़ से अधिक लाभ स्वीकृत किए जा चुके हैं। पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं तक पहुँच प्रदान कर यह पहल पथ विक्रेताओं और उनके परिवारों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का माध्यम बनी है।

इसके अतिरिक्त FSSAI के सहयोग से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं, जिससे विशेष रूप से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की गुणवत्ता, स्वच्छता और ग्राहक विश्वास में वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी योजना का योगदान उल्लेखनीय रहा है। कुल लाभार्थियों में लगभग 46 फीसदी महिलाएँ हैं। इससे उनकी आय, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है।

वर्ष 2023 और 2025 में की गयी इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट अस्सेस्मेंट्स ने भी योजना के दूरगामी प्रभावों की पुष्टि की है। लगभग 95 फीसदी लाभार्थियों ने अपने जीवन में पहली बार औपचारिक वित्तीय प्रणाली से ऋण प्राप्त किया, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इतना ही नहीं, बल्कि, लगभग 30 फीसदी लाभार्थी पीएम स्वनिधि से आगे बढ़कर अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थानों से भी ऋण प्राप्त करने में सफल हुए, जो उनके बढ़ते वित्तीय विश्वास और सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल का प्रमाण है।

योजना के लाभार्थियों की आय में औसतन लगभग 20ल वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही आवास, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सुधार देखा गया है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच यूपीआई आधारित लेन-देन का उपयोग लगभग 45ल से बढ़कर 83ल तक पहुँच गया है। योजना के व्यापक और सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके पुनर्गठित स्वरूप को मार्च 2030 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की।

पुनर्गठित योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के ऋण की सीमा में वृद्धि की गई है तथा योजना का दायरा शहरी स्थानीय निकायों से आगे बढ़ाकर Census Towns/Peri Urban तक विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही, क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि पथ विक्रेता बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उद्यमों को और अधिक सशक्त बना सकें। इसी क्रम में स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा पथ विक्रेताओं को उनकी तत्काल वित्तीय और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालिक ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है।

यद्यपि, पीएम स्वनिधि योजना ने सड़क विक्रेताओं को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान की है, फिर भी आज, कई जगह उन्हें शहर की नियोजन संरचना का हिस्सा नहीं माना जाता है। उन्हें सुनियोजित वेंडिंग स्थानों के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित स्थान न होने से उनकी आजीविका और ग्राहकों तक पहुँच प्रभावित होती है। इस चुनौती के समाधान हेतु आने वाले वर्षों में, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा पथ विक्रेताओं को शहरी नियोजन ढाँचे का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दिशा में एक छोटी सी पहल - स्ट्रीट फूड हब के माध्यम से उन्हें सुगम एवं व्यवस्थित व्यापारिक स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल उनकी आजीविका अधिक सुदृढ़ होगी, बल्कि शहरों की स्वच्छता, सुव्यवस्था और समग्र शहरी वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करती है। पीएम स्वनिधि की सफलता इस बात का प्रमाण है कि समावेशी विकास का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँच रहा है। पीएम स्वनिधि योजना ने पथ विक्रेताओं के लिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह योजना लाखों विक्रेताओं की आजीविका को सशक्त बनाते हुए नई परिवर्तनकारी कहानियाँ रचेगी तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- लेखक केंद्रीय आवासमंत्री हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

ट्रेनों की लेटलतीफी और 'रेल-वन' पर गलत जानकारी बनी यात्रियों की मुसीबत

दुर्ग। इन दिनों अधिकांश ट्रेनें निर्धारित समय से 15 मिनट से लेकर 2–2 घंटे की देरी से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ रेलवे के डिजिटल सिस्टम की खामी ने यात्रियों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। हद तो तब हो जाती है जब आईआरसीटीसी के 'रेलवन' और आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट भी ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। ट्रेन होती कहीं है और दिखाई कहीं और देती है। 10–15 मिनट लेट हो चुकी ट्रेन भी ऐप पर राइट टाइम चल रही होती है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से काम करें, व्यक्ति के लिए नहीं

भिलाई। भिलाई जिला भाजपा द्वारा जिला कार्यालय प्रियदर्शिनी परिसर, सुपेला में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 साल, विषय पर कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर जिला प्रभारी रामजी भारती ने कहा कि कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से काम करें, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर से मिले संदेश को जन–जन तक पहुंचाने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की उपलब्धियों को घर–घर बताने का आग्रह किया।

कांगो और युगांडा से आए दुर्ग के 3 लोगों में 'इबोला' वायरस

रायपुर/भिलाई। प्रदेश के दुर्ग जिले से बुधवार को एक बड़ी व चिंताजनक खबर सामने आई। कोरोना की तरह दुनिया के सबसे खतरनाक 'इबोला' वायरस ने कथित तौर पर दुर्ग में दस्तक दे दी है। कांगो, इथोपिया और युगांडा से उसके तीन संदिग्ध दुर्ग पहुंचे हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इबोला संदिग्धों के दुर्ग पहुंचने की पुष्टि की है। आईडीएसपी से सूचना मिलते ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी संदिग्धों को ढूंढ कर होम–आईसोलेशन में रखने निर्देश दिए हैं। केंद्र की सूचना के अनुसार इथोपिया व युगांडा से पहुंचे संदिग्ध अलग–अलग एयरपोर्ट होते हुए दुर्ग पहुंचे हैं, जबकि कांगो से निकला संदिग्ध मुंबई में ठहरा और फिर दुर्ग आया।

एनएल मौर्य का राष्ट्रीय ग्रेट अशोका अवार्ड के लिए चयन

भिलाई। भिलाई के वरिष्ठ साहित्यकार एनएल मौर्य 'प्रीतम' को राष्ट्रीय ग्रेट अशोका अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अशोक प्रबुद्ध समृद्ध भारत मिशन की ओर से यह सम्मान जबलपुर, मध्य प्रदेश स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय में 7 जून को आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित किया जाएगा।

एलडीसीपी के किल्न-3 का सफल पुनः प्रचालन

भिलाई इस्पात संयंत्र में 'जीरो हार्म' के साथ पूर्ण हुआ कैपिटल रिपेयर कार्य, ईडी ने दी बधाई

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र के लाइम एवं डोलो कैल्सिनेशन प्लांट (एलडीसीपी) के किल्न–3 का कैपिटल रिपेयर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत 02 जून 2026 को उसका पुन:प्रचालन विधिवत रूप से किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (संकार्य) राकेश कुमार ने किल्न को पुन: उत्पादन में प्रारंभ कर परियोजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न यह कार्य संयंत्र की तकनीकी क्षमता, टीमवर्क तथा उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति का परिचायक है।

पुन:प्रचालन समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (सेवाएँ) तुषार कांत, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (एम एंड यू) बिजय कुमार बेहेरा, मुख्य महाप्रबंधक (एसएमएस–2) सुशांत कुमार घोषाल, मुख्य महाप्रबंधक (रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग विभाग) प्रोसेनजीत दास, मुख्य महाप्रबंधक (कॉन्ट्रैक्ट सेल) इन्द्रजीत सेनगुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (ईएमडी) पीपीवीएस मूर्ति तथा मुख्य महाप्रबंधक (एसएमएस–3) त्रिभुवन बैठा उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक प्रभारी (आरएमपी–2 एवं आरएमपी–3) वीके ओगले ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। वहीं प्रबंधक (आरएमपी–3) विनय कुमार पवार द्वारा कैपिटल रिपेयर कार्य पर एक तकनीकी प्रस्तुति दी गई, जिसमें मरम्मत कार्य के विभिन्न चरणों, तकनीकी चुनौतियों, किए गए संशोधनों तथा प्राप्त परिणामों की विस्तृत जानकारी साझा की गई।

उल्लेखनीय है कि इस कैपिटल रिपेयर कार्य को सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 'जीरो हार्म' के लक्ष्य के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मरम्मत कार्य के दौरान रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा लगभग 1000 टन रिफ्रैक्टरी ईंटों के निष्कासन एवं पुन:स्थापन का चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संपन्न किया गया। विशेष रूप से, किल्न में पहली बार यंत्रीकृत (मेकनाइज्ड) पद्धति से डीब्रिकिंग कार्य किया गया, जिससे कार्य की दक्षता, सुरक्षा एवं निष्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

राकेश कुमार ने संयंत्र के प्रति स्वामित्व भाव विकसित करने तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कैपिटल रिपेयर कार्य को बिना किसी दुर्घटना अथवा चोट के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभागों, कर्मियों एवं सहयोगी एजेंसियों की सराहना की।

वरिष्ठ अधिकारियों ने इस उपलब्धि को उत्कृष्ट टीमवर्क, तकनीकी दक्षता, प्रभावी परियोजना प्रबंधन तथा मजबूत सुरक्षा संस्कृति का परिणाम बताया।

बीएसपी मेन हॉस्पिटल में हैंड्स ओनली सीपीआर का दिया प्रशिक्षण

सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता की पहल

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 'सेव ए लाइफ' पहल के अंतर्गत 'हैंड्स–ओनली सीपीसीआर (कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन)' प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 01 जून 2026 को अस्पताल के ओपीडी परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को उन महत्वपूर्ण जीवन–रक्षक कौशलों से परिचित कराना था, जिनकी सहायता से अचानक कार्डियक अरेस्ट जैसी आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकीय सहायता पहुंचने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सही तकनीक से चेस्ट कंप्रेशन देने, आपातकालीन प्रतिक्रिया की प्रक्रिया तथा प्रारंभिक जीवन रक्षक उपायों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार ने कहा कि कार्डियक आपातकाल की स्थिति में आसपास उपस्थित व्यक्ति ही सबसे पहले सहायता प्रदान कर सकता है। सही समय पर और सही तरीके से दिया गया सीपीसीआर किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने नागरिकों से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।

कार्यशाला में सभी आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उन्होंने मेडिकल मैनिक्विन पर सीपीसीआर का अभ्यास किया और तकनीकों को समझा। प्रतिभागियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की टीम ने कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला।

बिल्डिंग परमिशन के बिना नहीं मिलेगा नल कनेक्शन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 10 तक के विकास कार्यों एवं जनसमस्याओं की समीक्षा को लेकर महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने शुक्रवार शाम डाटा सेंटर में बैठक आयोजित की। बैठक में एमआईसी सदस्य, संबंधित वार्डों के पार्षद एवं निगम अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वार्डवार समस्याओं एवं आवश्यक विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में महापौर श्रीमती बाघमार ने वार्ड क्रमांक 1 से 10 तक के पार्षदों से बारी–बारी

उनके क्षेत्रों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। पार्षदों ने साफ–सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क एवं नाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, पाइपलाइन लीकेज, बोर रिपेयरिंग, सुलभ शौचालयों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था तथा नालियों की सफाई से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से रखा।

महापौर अलका बाघमार ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिना बिल्डिंग परमिशन किसी भी नए नल कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर निजी नल कनेक्शन होने के बावजूद सार्वजनिक नल चालू हैं, जिससे अनावश्यक जल व्यय हो रहा है। उन्होंने पानी का अपव्यय तत्काल रोकने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सुशासन शिविर : जामगांव आर को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की मांग

जामगांव आर। दक्षिण पाटन क्षेत्र के जामगांव आर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कामता प्रसाद साहू ने जामगांव आर में शासकीय अस्पताल की स्थापना और उपतहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने 35 ग्राम पंचायतों के सरपंचों से हस्ताक्षरित मांग पत्र मंच पर सौंपा।

बारिश में जलभराव रोकने नगर निगम युद्ध स्तर पर चला रहा नाला सफाई अभियान

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। आगामी मानसून को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक नाला सपाई अभियान शुरू कर दिया है। निगम के सभी 5 जोन क्षेत्रों में युद्धस्तर पर नालों की सपाई कराई जा रही है, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को जलभराव और उससे होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।

नालों में जमा जलकुंभी एवं कचरा को हटाने का कार्य लगातार जारी है। सफाई अभियान में निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों की संयुक्त टीम जुटी हुई है। बड़े एवं गहरे नालों की सफाई के लिए जेसीबी और चैन माउंटिंग मशीनों की सहायता ली जा रही है, जिससे नालों के मध्य भाग तक पहुंचकर प्रभावी सफाई की जा सके।

निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय ने सभी जोन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात शुरू होने से पहले नाला सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जल निकासी

व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना निगम की प्राथमिकता है और किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

निगम प्रशासन का कहना है कि नालों की समय पर सफाई होने से वर्षा जल का प्रवाह बाधित नहीं होगा और शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या काफी हद तक कम होगी। अभियान के तहत प्रमुख नालों के साथ–साथ आंतरिक कॉलोनियों के नालों की भी सफाई कराई जा रही है। निगम का लक्ष्य मानसून से पूर्व सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी कर बेहतर जल निकासी सुनिश्चित करना है।

खुर्सीपार में चला बुलडोजर, असामाजिक गतिविधियों का अड्डा ध्वस्त

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने जोन–4 खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 49 स्थित हार्ट बाजार के पास एक पुराने जर्जर भवन को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई क्षेत्र में लंबे समय से संचालित हो रही अवैध एवं असामाजिक गतिविधियों की शिकायत मिलने के बाद की। उक्त भवन काफी समय से जर्जर अवस्था में था और वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि भवन के भीतर शराबखोरी, गांजा सेवन और जुआ जैसी गतिविधियां संचालित हो रही थीं, जिससे आसपास के रहवासियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्र में कानून–व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी नागरिकों में चिंता लंबे समय से बनी हुई थी।

दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल ने भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण कर देखी देश की तकनीकी प्रगति

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल 'युवा संगम फेज–6' के अंतर्गत दिल्ली से आए 60 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण कर देश की औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक–दूसरे की संस्कृति, विकास यात्रा, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक उपलब्धियों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई ने छत्तीसगढ़ के नोडल उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा आईआईटी दिल्ली के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत मानव संसाधन–ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को औद्योगिक सुरक्षा, कार्यस्थल सावधानियों तथा संयंत्र भ्रमण के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सभी प्रतिभागियों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए, जिससे वे सुरक्षित रूप से संयंत्र की उत्पादन इकाइयों का अवलोकन कर सकें।

प्रतिनिधिमंडल ने संयंत्र की विभिन्न उत्पादन इकाइयों का भ्रमण किया। विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को इस्पात निर्माण की आधुनिक प्रक्रियाओं, भारी इंजीनियरिंग, धातुकर्म तकनीकों तथा उत्पादन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। युवाओं ने इस्पात उत्पादन गतिविधियों, आधुनिक तकनीकी प्रणालियों तथा राष्ट्रीय आधारभूत संरचना निर्माण में भिलाई इस्पात संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को निकट से समझा।

घटना से एक दिन पहले ही लगा था रक्तदान शिविर, 81 यूनिट हुआ था संग्रह

रक्त नहीं मिलने से युवती की मौत पर रक्तदाता दुखी

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। अय्यूब खान, सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ ने बताया कि दुर्ग जिला अस्पताल में रक्त उपलब्ध न होने के कारण एक युवती की मृत्यु होना अत्यंत चिंताजनक एवं दुखद घटना है। दुखद मृत्यु की घटना के एक दिन पूर्व भिलाई स्थित चौहान होटल में 'ऑथ वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन' द्वारा विशाल रक्तदान शिविर दिनांक 31/05/2026 को लगाया गया था। इस शिविर में मेरे अलावा जिले के अनेक जनप्रतिनिधिगण एवं जिला ब्लड बैंक प्रभारी मेश्राम स्वयं उपस्थित थे।

जिसमें लगभग 83 यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उसके बावजूद दूसरे दिन 1 जून को

उसी जिला अस्पताल में रक्त उपलब्ध न होने से किसी मरीज की मृत्यु हो जाना बहुत दुखद और चिंताजनक है।

मेरी जिला प्रशासन से माँग है कि जब 'ऑथ वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन' ने 81 यूनिट रक्तदान किया था, ठीक उसके दूसरे दिन ब्लड की मात्र 1 यूनिट इस मरीज को नहीं देना जाँच का विषय है। इसमें अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही और रक्त की कालाबाजारी होने का आभास हो रहा है। इसकी जाँच जिला प्रशासन के कलेक्टर को करनी चाहिए। जिसकी भी इस घटना में लापरवाही एवं जिम्मेदारी बनती है, उस पर तत्काल कार्रवाई कर नौकरी से निष्कासित करना चाहिए।

अय्यूब खान, सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ ने आगे कहा कि शासन और प्रशासन यदि इस विषय को गंभीरता से नहीं लेगा तो जो सामाजिक संस्थाएँ और राजनीतिक पार्टियाँ रक्तदान शिविर लगाती हैं, उन मरीजों को तत्काल रक्त अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। रक्त उपलब्ध होते हुए भी मरीजों को न देना सामाजिक संस्थाओं एवं रक्तदाताओं का मनोबल तोड़ देगा। इसी कारण को देखते हुए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

बधिर टी-20 चैम्पियंस ट्रॉफी में डी टीम बनी उपविजेता, भिलाई के सिद्धार्थ भी रहे शामिल

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित टी–20 चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया डी टीम को उपविजेताका खिताब मिला है। इस टीम में भिलाई के क्रिकेटर सिद्धार्थ श्रीवास्तव शामिल थे। यह टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण था। बी टीम ने फाइनल में 'इंडिया डी' को 32 रनों से हराया।

सिद्धार्थ ने इससे पहले अपनी टीम की कप्तानी भी की है। डोंगरगांव के योगेन्द्र देवांगन सी टीम में खेल रहे थे। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए) टी–20 चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत की चार टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट अक्टूबर में यूएई में होने वाले आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफायर भी था।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

कच्चे घर से खुशियों के आशियाने तक : महादेई के सपनों को मिला नया आसमान

रायपुर। एक मजबूत घर केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीदों का आधार होता है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ऐसी ही उम्मीदों को साकार कर रही है। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम पुतकी की निवासी महादेई गुर्जर की कहानी इस परिवर्तन की प्रेरक मिसाल है। कभी कच्चे मकान में रहने वाली महादेई का परिवार हर बरसात में चिंता और असुरक्षा के बीच जीवन बिताता था। बारिश के दिनों में छत से टपकता पानी, कमजोर दीवारें और घर के ढहने का भय उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण पक्का घर बनाना उनके लिए एक दूर का सपना था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वर्ष 2024-25 में आवास स्वीकृत होने के बाद शासन की मदद और मनरेगा के माध्यम से प्राप्त मजदूरी सहायता से उनका सपना धीरे-धीरे आकार लेने लगा। मेहनत, उम्मीद और सरकारी सहयोग के संगम ने आखिरकार उस सपने को हकीकत में बदल दिया, जिसका इंतजार महादेई का परिवार वर्षों से कर रहा था।

सुशासन तिहार 2026 : सुरनार समाधान शिविर में उमड़ा ग्रामीणों का उत्साह

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत सुरनार में आयोजित क्लस्टर स्तरीय समाधान शिविर में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। शिविर में आसपास के सात ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री चैतराम अटामी शामिल हुए। इस अवसर पर जनपद पंचायत कटेकल्याण के उपाध्यक्ष श्री भीमसेन मंडावी, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस शिविर में कुल 221 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 216 मांग संबंधी और 5 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल हैं। शिविर में ग्राम पंचायत धनीकरका, दुवालीकरका, बुरदीकरका, नड़ियापदर, सुरनार, गाटम और बड़ेलखापाल के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे।

नैनो उर्वरकों ने बदली खेती की दिशा कम लागत, बेहतर फसल और बढ़ता मुनाफा

रायपुर। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के छोटे से गांव सोनकापारा में रहने वाले प्रगतिशील किसान छत्रदास कुर्रे आज आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। खेती में नई तकनीकों को अपनाने की उनकी सोच ने न केवल उनकी फसल की गुणवत्ता सुधारी है, बल्कि खेती को अधिक लाभकारी भी बना दिया है। छत्रदास कुर्रे बताते हैं कि उन्होंने पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का संतुलित उपयोग किया। शुरुआत में उन्हें इस नई तकनीक को लेकर कुछ संदेह था, लेकिन फसल के बढ़ते हुए पौधों ने जल्द ही उनके सभी सवालों का जवाब दे दिया। खेत में फसल की बढ़वार पहले की तुलना में बेहतर रही, पौधे अधिक हरे-भरे और मजबूत दिखाई दिए तथा उत्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार सतर्क

वैश्विक परिस्थितियों के बीच खाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर काम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को समय पर खाद एवं कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आगामी खरीफसीजन को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मार्कफेड तथा जिला प्रशासन के समन्वय से पूरे प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

राज्य सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों के कारण रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावनाओं को देखते हुए अग्रिम तैयारी की है। उर्वरकों के पर्याप्त भंडारण, समयबद्ध परिवहन और किसानों तक सुगम वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों, कृषि अधिकारियों, सहकारिता विभाग तथा मार्कफेड को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर रोक लगाने के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। वर्तमान में राज्य में 9.29 लाख मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का स्टॉक गोदामों और सोसायटियों में उपलब्ध है। जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को इस खरीफ सीजन के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आबंटित हुआ हजिसमें यूरिया 7.25 लाख, डीएपी 3 लाख, एमओपी 80 हजार, एनपीके 2.5 लाख तथा एसएसपी 2 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश के गोदामों एवं समितियों में लगभग 9.29 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है।

कृषि विभाग के संचालक राहुल देव ने बताया कि किसानों को पर्याप्त खाद्य मिले इसके लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जून 2026 अंतर्गत 1 जून 2026 की स्थिति में रेक प्वाइंट तिल्दा, जिला रायपुर में 1319 मीट्रिक टन यूरिया, रेक प्वाइंट बेलसोंडा महासमुंद 1316 मीट्रिक टन यूरिया इसी प्रकार रेक प्वाइंट खरसिया, जिला रायगढ़ 2646 मीट्रिक टन यूरिया और रेक प्वाइंट जिला बालोद में 1319 मीट्रिक टन यूरिया, इस तरह कुल 6600 मीट्रिक टन यूरिया की खेप आने वाली हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गरियाबंद जिले में वर्तमान में 17,818 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक तथा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसी प्रकार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की मुकुरमुडा समिति में खरीफ सीजन के लिए 362 मीट्रिक टन उर्वरकों का अग्रिम भंडारण किया गया है। किसानों को गांवों के निकट ही खाद उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त गोदामों की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मुंगेली जिले में यूरिया वितरण के दौरान तकनीकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हुई अस्थायी स्थिति का तत्काल समाधान कर प्रशासन एवं कृषि विभाग की निगरानी में किसानों को व्यवस्थित रूप से खाद उपलब्ध कराया गया। बस्तर जिले में खरीफ 2026 हेतु उर्वरक भंडारण एवं वितरण का कुल लक्ष्य 46,050 मीट्रिक टन निर्धारित है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के पास 18,341 मीट्रिक टन तथा मार्कफेड एवं थोक विक्रेताओं के पास 11,378 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में कुल 29,719 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 64 प्रतिशत है।

रायपुर जिले में यूरिया की समितियों में वर्तमान उपलब्धता 9,102 मीट्रिक टन है, जबकि संग्रहण केंद्रों से कुल 10,732 मीट्रिक टन यूरिया भंडारित किया गया है। इसी प्रकार डी.ए.पी. की समितियों में वर्तमान उपलब्धता 3,092 मीट्रिक टन है, जबकि कुल भंडारित मात्रा 3,927 मीट्रिक टन है। किसानों की सुविधा और सुचारू वितरण व्यवस्था के लिए भूमि की उपलब्धता के आधार पर यूरिया के वितरण की किश्तें भी निर्धारित की गई हैं। इसके तहत ढाई एकड़ तक की भूमि वाले सीमांत कृषकों को निर्धारित यूरिया की मात्रा एकमुश्त प्रदाय की जाएगी। ढाई एकड़ से पांच एकड़ तक की भूमि वाले लघु कृषकों को उर्वरक का उठाव दो किश्तों में करने की सुविधा होगी, जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले बड़े कृषकों को यूरिया का प्रदाय तीन किश्तों में सुगमतापूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा।

राजनांदगांव जिले में खरीफ वर्ष 2026 हेतु 68690 मेट्रीक टन का लक्ष्य रखा गया है, जिले में अद्यतन सहकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर 42997 मेट्रीक टन खाद उपलब्ध है, जिसमें 17559 मेट्रिक टन यूरिया, 4271 मेट्रिक टन डीएपी, 10578 मेट्रिक टन एनपीके, 3471 मेट्रिक टन एमओपी एवं 7119 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद उपलब्ध हैं, जो गतवर्ष इसी अवधि की तुलना से 43ः अधिक हैं। सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को लगातार खाद वितरण किया जा रहा है, जिले में 10874 किसानों को खाद प्रदाय किया जा चुका हैं, जिसमें 7193 मेट्रिक टन यूरिया, 1807 मेट्रिक टन डीएपी, 4669 मेट्रिक टन एनपीके, 1322 मेट्रिक टन एमओपी एवं 2214 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद किसानों को खरीफ फसलों हेतु वितरण किया जा चुका है तथा जिले में उर्वरकों की कमी नहीं हैं।

कोरिया जिले में सभी उर्वरकों को मिलाकर कुल 12,150 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 6,196 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। लक्ष्य की तुलना में लगभग 5,530 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण शेष है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी समितियों में खाद भंडारण एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। खरीफ 2026 के लिए बिलासपुर जले को 68,950 टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सके विरुद्ध अब तक 46,780 टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 60.28 प्रतिशत है। वहीं किसानों को अब तक 19,912 टन से अधिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है।जिले में वर्तमान में कुल 41,560 टन उर्वरक का भंडार उपलब्ध है। इनमें यूरिया 22,996 टन, डीएपी 5,621 टन, एनपीके 6,808 टन, एसएसपी 4,981 टन तथा एमओपी 1,155 टन शामिल है। कृषि विभाग द्वारा लगातार उर्वरक कंपनियों से अतिरिक्त रैक प्राप्त कर भंडारण बढ़ाया जा रहा है ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

जिला कोरबा में 1 अप्रैल से 31 मई 2026 तक कुल 2101.85 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया गया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में सर्वाधिक 1165.85 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया। इसके अलावा 310.85 मीट्रिक टन डीएपी, 67.75 मीट्रिक टन एमओपी, 437.70 मीट्रिक टन एसएसपी तथा 119.70 मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराया गया।

साय सरकार की बड़ी राहतः महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री में 70 प्रतिशत भारी वृद्धि

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों के जमीन पर सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर महिलाओं के नाम होने वाली भूमि व संपत्ति की रजिस्ट्री (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने और 12 प्रतिशत उपकर को पूरी तरह समाप्त करने के निर्णय से बड़ा बदलाव आया है। शासन की इस बड़ी रियायत के चलते बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने और पंजीयन कराने की होड़ सी मच गई है। आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।

जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह छूट लागू होने के बाद मात्र एक महीने के भीतर महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल 2026 जिले के पांचों उप पंजीयक कार्यालयों में महिलाओं के नाम पर कुल 309 दस्तावेज पंजीकृत हुए थे। मई 2026 यह संख्या बढ़कर 445 पहुंच गई, जो अप्रैल की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाती है।

रजिस्ट्री शुल्क में कटौती का लाभ उठाने में जिले के सभी क्षेत्र आगे रहे हैं, जिनमें शहरी इलाकों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। उप पंजीयक कार्यालय केवल बलौदाबाजार में अप्रैल 2026 में 78 और मई 2026 में बढ़कर 119 हो गया। इसी प्रकार पलारी में अप्रैल 2026 में 40 दस्तावेज बढ़कर मई 2026 में 56, सिमगा में 56 से बढ़कर 99, कसडोल में 24से बढ़कर 50 तथा भाटापारा में 111 से बढ़कर 121 दस्तावेज हो गए। यह वृद्धि दर्शाती है कि महिलाओं को दी गई पंजीयन शुल्क छूट का लाभ बड़ी संख्या में परिवार उठा रहे हैं। शहरी क्षेत्र बलौदाबाजार और भाटपारा के आकड़ों में अधिक वृद्धि देखी गई है।

जिला पंजीयक विनोद कोचे ने बताया कि राज्य शासन की इस नीति का सीधा और त्वरित लाभ महिलाओं को मिल रहा है। संपत्ति खरीद की लागत काफी कम हो जाने से अब परिवार स्वेच्छा से महिलाओं के नाम पर जमीन और मकान पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

वहीं, बलौदाबाजार के उप पंजीयक विपुल श्रीवास्तव के अनुसार, अप्रैल 2026 से 12 प्रतिशत उपकर समाप्त होने से इस प्रक्रिया में और तेजी आई है। अकेले बलौदाबाजार कार्यालय में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक 107 अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। खास बात यह है कि इससे जहां एक तरफ आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने से शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है।

योजना की लाभार्थी नमिता साहू ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर मिलने वाली इस छूट से उनके परिवार को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है। पहले रजिस्ट्री में भारी-भरकम खर्च देखकर लोग कतराते थे, लेकिन अब खर्च आधा होने से यह बेहद आसान हो गया है। इससे महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, बल्कि संपत्ति पर उनका कानूनी अधिकार भी मजबूत हो रहा है।

बाल विवाह पर सख्तीः समय रहते रोका गया विवाह, नाबालिग का भविष्य हुआ सुरक्षित

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती और जनजागरूकता के प्रयास लगातार प्रभावी साबित हो रहे हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से एक नाबालिग का विवाह रुकवाया गया, जिससे उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित किया जा सका।

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में प्राप्त सूचना पर पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में बालक की आयु निर्धारित वैधानिक विवाह आयु से कम पाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह कराना, उसमें सहयोग करना अथवा उसका आयोजन करना कानूनन दंडनीय अपराध है।

समझाइश और परामर्श के बाद परिजनों ने बालक का विवाह निर्धारित वैधानिक आयु पूर्ण होने के बाद ही करने की सहमति व्यक्त की। प्रशासन की इस समयबद्ध कार्रवाई से एक संभावित बाल विवाह को रोका जा सका। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

सुशासन तिहार बना बुजुर्गों का सहारा, 74 वर्षीय कोटवार को मिला श्रवण यंत्र

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और जरूरतमंदों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत पीढ़ा निवासी 74 वर्षीय कोटवार जानकी को श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) प्रदान किया गया, जिससे उन्हें सुनने में होने वाली परेशानी से राहत मिली है।

श्री जानकी ने सुशासन तिहार के दौरान श्रवण संबंधी समस्या के समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होते ही जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया गया। इससे अब उन्हें दैनिक गतिविधियों के संचालन और लोगों से संवाद स्थापित करने में काफी सुविधा होगी। श्रवण यंत्र प्राप्त करने के बाद जानकी ने शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से सुनने में कठिनाई होने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उनकी परेशानी काफी हद तक दूर हो गई है।

सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेशभर में प्राप्त आवेदनों के त्वरित और प्रभावी निराकरण से लोगों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

छत्तीसगढ़ में बाल संरक्षण की नई मिसाल : पहली बार समुदाय-आधारित फोस्टर केयर के तहत बालक को मिला पारिवारिक संरक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिले में पहली बार समुदाय-आधारित फोस्टर केयर (पोषण देखरेख) प्लेसमेंट सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसके तहत एक जरूरतमंद बालक को विधिवत उसी समुदाय के एक योग्य फोस्टर पालक परिवार की देखरेख में सौंपा गया।

यह पहल इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि बालक और फोस्टर पालक दोनों एक ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े हैं। इससे बच्चे को न केवल परिवार जैसा स्नेह और सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वह अपने समुदाय, संस्कृति और सामाजिक पहचान से भी जुड़ा रहेगा। बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम माना जा रहा है।

इस ऐतिहासिक प्लेसमेंट प्रक्रिया को जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) रायगढ़ के मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया। समिति के अध्यक्ष गेवेश नायक तथा सदस्यों लक्ष्मी प्रसाद पटेल, निवेदिता पटनायक एवं रूपलाल चौहान ने मामले का विस्तृत परीक्षण कर सभी आवश्यक दस्तावेजों और विधिक प्रावधानों का सत्यापन किया तथा फोस्टर केयर प्लेसमेंट को स्वीकृति प्रदान की। जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर. कच्छप के निर्देशन और जिला बाल संरक्षण अधिकारी धीरेन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नियमानुसार संपन्न कराया गया। प्रारंभिक प्रयास ऑनलाइन माध्यम से किए गए, किंतु तकनीकी एवं सर्वर संबंधी बाधाओं के कारण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। ऐसे में बालक के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखते हुए निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार फॉर्म-32 के माध्यम से ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी कर बालक को पोषण देखरेख में सौंपा गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों सहित खुशीराम साहू, दूबीश्याम खड़िया, किरण मेहर एवं सविता साव (सीईएसी) की सक्रिय सहभागिता रही। गृह सत्यापन, दस्तावेजीकरण और समन्वय में उनके योगदान ने इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विकास कार्यों में नही होगी कोई कमी-मंत्री टंक राम वर्मा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की जनता की समस्याओं के त्वरित और मौके पर ही निराकरण के लिए 'सुशासन तिहार' के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्राम छेरकापुर में एक विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

शिविर के दौरान राजस्व मंत्री वर्मा ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 55 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। साथ ही, विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे पहुंचकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक लेना और समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। हमारा प्रयास है कि युवा, गरीब, बच्चे और किसान,समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने सेमरिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 30 लाख रुपये और गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर के विकास हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, छेरकापुर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, छेरकापुर में मुक्तिधाम निर्माण और सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की तकलीफों का जमीनी स्तर पर समाधान करना है।'विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी' के तहत राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुँच रहा है।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और अभियानों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 'मोर गाँव मोर पानी अभियान 2.0' के तहत जल संचयन दीदियों और ग्राम पंचायतों के साझा प्रयासों से महज ढाई महीने के भीतर ढाई लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जारी 'हम होंगे कामयाब 2.0' वेब पोर्टल की भी जानकारी दी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल रही हैं। इस समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया और बड़ी संख्या में हितग्राहियों को सीधे लाभान्वित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श देने के साथ ही आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल बांटी गई। इसके अलावा, 'हम होंगे कामयाब' अभियान 2.0 के तहत युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट सौंपे गए। खेल विभाग द्वारा स्थानीय खेल प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं, राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड और डिजिटल किसान किताब का वितरण किया गया।

तृषा कृष्णन का ट्रोलर्स को जवाब

विजय से नाम जुड़ने के बीच कुत्ते की तस्वीर के साथ लिखा- सिर्फ इसे मेरी जिंदगी में दखल देने की इजाजत

साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ अपने रिश्ते की ट्रोलिंग पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। तृषा ने अपने पालतू डॉग की एक फोटो शेयर कर लिखा कि सिर्फ इसी को मेरी जिंदगी में दखल देने की इजाजत है।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर विजय और तृषा के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हाल ही में दोनों को एक्टर अजीत कुमार के घर पर भी साथ देखा गया था।

इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की स्टोरी तृषा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उनका पालतू डॉग बेड पर आराम करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के साथ तृषा ने लिखा, एकमात्र नाक जिसे मैं अपने काम में दखल देने की इजाजत देती हूं। यूजर्स इस पोस्ट को उन लोगों के ट्रोलर्स के लिए सीधा जवाब मान रहे हैं जो पिछले काफी समय से उनकी पर्सनल लाइफको लेकर कयास लगा रहे हैं।

अजीत कुमार की मां के निधन पर साथ पहुंचे थे दोनों यह पूरा मामला तब दोबारा चर्चा में आया जब विजय और तृषा को चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार के घर पर देखा गया। अजीत कुमार की मां मोहिनी मणि का हाल ही में निधन हो गया है। इस दुखद खबर के बाद अजीत दुबई से तुरंत चेन्नई लौटे थे। फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति से जुड़े कई लोग अजीत के घर संवेदना जताने पहुंचे। इसी दौरान विजय भारी सुरक्षा के बीच वहां पहुंचे और अजीत को गले लगाकर ढांढस बंधाया। उनके कुछ देर बाद तृषा भी ब्लैक कलर के सलवार सूट में अजीत के परिवार से मिलने पहुंची थीं। बर्थडे और शपथ ग्रहण समारोह से बढ़ीं अफवाहें विजय और तृषा के बीच नजदीकियों की खबरें पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं। मई में तृषा के बर्थडे के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तिरुमला मंदिर के दर्शन करने के बाद तृषा को चेन्नई में विजय के घर से निकलते हुए देखा गया था।

इसके अलावा जब विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी के लिए शपथ ग्रहण समारोह रखा था, तब भी तृषा अपनी मां उमा कृष्णन के साथ वहां मौजूद थीं। इन दोनों ही वाकयों के बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई थी।

हालांकि, रिश्ते की अफवाहों पर न तो विजय ने और न ही तृषा ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान दिया है। दोनों ही इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

'अजूबा' की सोनम खान ने पीक पर क्यों छोड़ी थी फिल्में?

90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस सोनम खान ने फिल्म 'अजूबा' में ऋषि कपूर के साथ फिल्माए गए अपने मशहूर बाथटब सीन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री से क्यों दूरी बनाई थी इसकी वजह भी सामने आ गई है।

फिल्म 'त्रिदेव' का वो सुपरहिट गाना 'ओए-ओए' और उस पर थिरकने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस सोनम खान तो अच्छी तरह याद होंगी। सोनम ने 'विश्वात्मा', 'क्रोध' और अमिताभ बच्चन-ऋषि कपूर स्टारर 'अजूबा' जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम करके बहुत कम समय में बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। उन्होंने मशहूर डायरेक्टर राजीव राय से शादी कर ली। सोनम ने बताया कि शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपनी फैमिली पर फोकस करने का फैसला किया और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। शादी के बाद वह अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गईं, ताकि एक नॉर्मल और शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकें। हालांकि, उनका यह सफर उतना आसान नहीं रहा जितना दिखता था।

35 साल पुराने बाथटब सीन का भी खोला राज

सोशल मीडिया पर अपनी वापसी के बाद सोनम लगातार अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म 'अजूबा' के उस मशहूर बाथटब सीन का भी सच बताया जिसे उस दौर में बहुत बोल्ड माना गया था। उन्होंने साफकिया कि ऋषि कपूर के साथ इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने स्किन कलर की लेगिंग्स और बस्टियर पहना हुआ था और वे पूरी तरह कपड़ों में थीं। सोनम की इस बेबाकी और अपनी लाइफके संघर्ष को मुस्कुराकर बयां करने के अंदाज ने आज के युवाओं और उनके पुराने फैंस का दिल एक बार फिर जीत लिया है।

'जरूरी नहीं कि आपको परफेक्ट होना ही चाहिए' जोक मारने पर ट्रोल हुए थे विक्की कौशल

मार्च में अभिनेता विक्की कौशल का शादी पर जोक मारते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। अभिनेता ने इस पर अब रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है?

अभिनेता विक्की कौशल अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने शादी को लेकर किए गए जोक पर ट्रोल होने के मामले पर अब अपनी बात रखी है। विक्की कौशल का इस साल मार्च में एक वीडियो सामने आया था। इसमें वह शादी पर जोक मारते हुए नजर आए थे। इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस मामले पर उन्होंने कहा कि किसी पब्लिक फिगर के लिए हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं है।

आलोचना के हकदार होते हैं

विक्की कौशल ने कहा कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं, इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा 'ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको परफेक्ट होना ही चाहिए। कभी-कभी हम आलोचना के हकदार होते हैं। शायद मेरे लिए इसमें सीखने वाली बात यह है कि जितना लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, उसके साथ एक खास तरह की जिम्मेदारी भी आती है।'

आलोचना से सीख सकते हैं

उन्होंने आगे कहा 'किसी भी एक्टर को शोहरत मिली हो और उसे उसका दूसरा पहलू न देखना पड़ा हो, ऐसा नहीं होता। मैंने सोच-समझकर यह फैसला किया था कि मुझे यहां रहना है। अब यह मुझ पर है कि मैं (शोहरत) को कैसे संभालता हूं। अगर आलोचना रचनात्मक है, तो आप उससे सीख सकते हैं।'

वायरल हुए वीडियो में विक्की कौशल ने वहां मौजूद लोगों से पूछा था' हाउज द जोश?' इस बात पर लोगों ने जवाब दिया था 'हाई सर।' फिर विक्की ने मजाकिया अंदाज में कहा 'मैंने देखा है कि बैचलर्स का जोश हमेशा हाई रहता है। हम शादीशुदा लोगों का जोश साल दर साल कम होता रहता है। (दूल्हे की तरफ इशारा करते हुए) लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, 4 दिन में जोश कम नहीं होता।' विक्की के इस जोक को लोगों ने सोशल मीडिया पर पसंद नहीं किया था।

विकी कौशल का वर्कफ्रंट

विकी कौशल जल्द ही संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे। इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस रोमांटिक ड्रामा के इस साल रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है। अब यह जनवरी 2027 में रिलीज होगी।

कंगना रनौत की पहली फिल्म देख पैरेंट्स हुए नाराज

गैंगस्टर को लेकर कहा था- समाज क्या सोचेगा, उनकी बेटी कैसी फिल्में कर रही है

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट ने अपनी डेब्यू फिल्म गैंगस्टर को लेकर बताया कि यह फिल्म देखने के बाद उनके माता-पिता खुश नहीं थे और फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर चिंतित थे।

अपनी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने बताया, गैंगस्टर देखने के बाद मेरे पिताजी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। फिर मैंने माताजी से पूछा, मम्मी, आपको मेरी फिल्म कैसी लगी? तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम अभी बहुत छोटी थीं, अंडरएज भी थीं। तुमसे इस तरह के सीन करवा लिए गए।

एक्ट्रेस ने कहा, मैंने कहा, पूरी फिल्म में आपको वही सीन दिखे? सच कहूं तो मेरा दिल टूट गया था। मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने उस फिल्म को इस तरह देखा क्योंकि वे लोग सोच रहे थे कि समाज क्या सोचेगा, कि उनकी बेटी कैसी फिल्में कर रही है।

कंगना ने कहा कि उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह अपनी फिल्मों को लेकर माता-पिता से किसी खास प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करेंगी, क्योंकि उनका परिवार फिल्मी दुनिया से नहीं जुड़ा था।

'क्वीन' के लिए मिला था अमिताभ बच्चन का पत्र

एक्ट्रेस ने बताया कि जब मुझे फिल्म 'क्वीन' के लिए अमिताभ बच्चन जी का एक खूबसूरत पत्र मिला, जिसमें उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस की तारीफकी थी, तब मैंने सोचा कि जिस तरह अमिताभ बच्चन मेरे काम को समझ सकते हैं, मेरे पिताजी वैसा नहीं समझ सकते और इसके लिए मैं उनसे नाराज भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह कलाकार नहीं हैं। उनका अपना अलग काम है।

नेशनल अवॉर्ड मिलने पर परिवार खुश हुआ

कंगना ने यह भी बताया कि समय के साथ उनके माता-पिता की सोच बदली। जब उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला तो उनका परिवार बेहद खुश हुआ। उन्हें लगा कि उनकी बेटी को देश के राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला है। इसके बाद जब कंगना को पद्मश्री पुरस्कार मिला तो यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

उनके मुताबिक, तब उनके माता-पिता को एहसास हुआ कि फिल्मों में काम करते हुए भी सम्मान, पहचान और बड़े नागरिक सम्मान हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनके परिवार ने उनके काम को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया।

'भारत भाग्य विधाता' में आएंगी नजर

कंगना रनोट की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म संकट की स्थिति में एक सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई हिम्मत और मानवता की कहानी पर आधारित है।

डायरेक्टर मनोज तापड़िया की इस फिल्म में गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे और आशा शेलार भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

धुरंधर फेम आयशा खान को फैन से मिला प्यारा गिफ्ट

एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल......

'धुरंधर' फेम आयशा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन उन्हें एयरपोर्ट पर बैग गिफ्ट करता नजर आ रहा है। फैन के सरप्राइज गिफ्ट पर एक्ट्रेस का प्यारा रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है।

बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक पाने, उनसे मिलने के लिए हमेशा एक्ससाइटेड रहते हैं। ऐसा ही कुछ 'धुरंधर' में अपने डांस का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम आयशा खान के फैंस का भी हाल रहता है। आयशा खान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। आदित्य धर और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के पॉपुलर आइटम सॉन्ग 'शरारत' में अपने जबरदस्त डांस मूव्स से रातों रात फेमस हो चुकी हैं आयशा खान। आज आलम ये है कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वाले घंटो इंतज़ार करते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी पोस्ट या फोटो पर भर-भर कर कमेंट्स करते हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयशा खान एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ब्लू डेनिम लूज पैंट और ब्लैक जैकेट पहना हुआ है। इस वीडियो में आयशा खान का एक जबरा फैन उनसे मिलने के लिए आता है और उनको एक बैग गिफ्ट करता है। बैग देखकर एक बार तो आयशा हिचकिचाती हैं लेकिन फैन के प्यार और सम्मान को देखते हुए उन्होंने वो बैग लिया और बड़े ही सजह अंदाज में उसको थैंक यू कहा।

`देखते ही देखते आयशा खान और उनके फैन का ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो पर यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कोई इस पर कमेंट कर रहा है कि 'हर किसी को ऐसा प्यार नहीं मिलता', तो कोई बोल फैन पर टिप्पणी करते हुए कह रहा है कि ये गरीब अपनी हरकत से गरीब होते हैं।'

जबकि एक यूजर ने लिखा, 'ये सब मुनव्वर की वजह से हुआ है, इसमें इसकी कोई खास मेहनत नहीं है। ये बात सब जानते हैं। इसे पहले कौन जानता था? मुनव्वर की वजह से ही इसे बिग बॉस में आने का मौका मिला। सिर्फ फेमस होने के लिए इसने ड्रामा किया। कोई भी समझदार लड़की सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा नहीं करती। आखिर इसकी खुद की मेहनत क्या है?'

आयशा खान के बारे में

आयशा खान का करियर काफी संघर्ष भरा रहा है। उन्होंने एकता कपूर के शो 'कसौटी जिंदगी की' में एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी। इसके बाद 'बालवीर रिटर्न्स' और तेलुगू फिल्म 'मुखचित्रम' की। 'बिग बॉस' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, जिसके बाद उन्होंने 'जाट', 'गैंग्स ऑफ गोदावरी' और 'किस किसको प्यार करूं 2' जैसी फिल्मों में काम किया।

सलमान खान को बड़ी राहतः एफएसएल जांच के लिए नहीं आना पड़ेगा कोटा, 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद फिलहाल उन्हें एफएसएल जांच के लिए कोटा नहीं आना होगा। कंज्यूमर कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई तय की है।

राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कोटा की उपभोक्ता अदालत (कंज्यूमर कोर्ट) में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र और राजस्थान हाईकोर्ट के स्थगन आदेश (स्टे) को अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही फिलहाल सलमान खान को एफएसएल जांच के लिए कोटा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से कंपनी के अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पूर्व आदेश पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट से प्राप्त स्थगन आदेश की प्रति भी अदालत के समक्ष पेश की गई। अदालत ने दोनों दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई निर्धारित की है।

27 मई को अंतरिम राहत को मिली थी अंतरिम राहत

अधिवक्ता राकेश सुवालका के अनुसार, इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने पहले अदालत में अवमानना संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद सलमान खान की ओर से संबंधित कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 27 मई को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए स्थगन आदेश जारी किया था।

दरअसल, विवाद सलमान खान की ओर से उपभोक्ता अदालत में प्रस्तुत वकालतनामा और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर है। याचिकाकर्ता पक्ष ने हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 26 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच कराने और अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षरित शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे।

बाद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। इसी मामले में मंगलवार को आगे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद फिलहाल अभिनेता को राहत मिल गई है। अब इस मामले में सभी की नजर 14 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला हो सकता है।

खास खबर

आजादी के 78 साल बाद रोशन होंगे दूरस्थ मजराटोले, सुशासन तिहार में जिले को मिली बड़ी सौगात

रायपुर। सुशासन तिहार-2026 के अवसर पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के समन्वित प्रयासों से जिले के 10 दूरस्थ एवं अब तक विद्युत सुविधा से वंचित मजराटोलों के विद्युतीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन क्षेत्रों में इसी सत्र के दौरान तेजी से विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण किया जाएगा। आजादी के 78 वर्षों बाद जिले के ऐसे दूरस्थ वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जहां अब तक अंधेरा ही ग्रामीणों की नियति बना हुआ था। मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत निजामडीह, तुम्दादाह, बलरामपुर, कोहकझोरी, संजारी-टाटीघाट, झिलमिली एवं गाताभर्री, घाघरा, लमरा, रिहाडबरा तथा टिनगीपुर जैसे गांवों के मजराटोलों में विद्युत नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। विद्युतीकरण से न केवल घरों में रोशनी पहुंचेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और आजीविका के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। बिजली उपलब्ध होने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सुविधाएं, छोटे व्यवसाय और शासकीय सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा।

सुशासन तिहार के माध्यम से घर-घर पहुंच रही स्वास्थ्य सुरक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित सुशासन तिहार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के अंतर्गत गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत आमाडोब निवासी झिलमित मरावी को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया, जिससे उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण संबल मिला है। यह कार्ड उनके लिए केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सुरक्षा की नई उम्मीद लेकर आया है। आयुष्मान कार्ड प्राप्त होने के बाद अब वे और उनका परिवार देशभर के चिन्हित अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

हाथियों के साये से सुरक्षित भविष्य तक : पीएम आवास योजना ने दिया नया जीवन

रायपुर। घने जंगलों से घिरे सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम सिंघरा में रहने वाले करमचन्द्र और उनका परिवार वर्षों तक भय और असुरक्षा के बीच जीवन बिताता रहा। यह क्षेत्र हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्ग (एलीफेंट कॉरिडोर) में स्थित है, जहाँ हर वर्ष हाथियों की आवाजाही ग्रामीणों के लिए चिंता और चुनौती का कारण बनती है। ऐसे में मिट्टी और खपरैल से बने जर्जर कच्चे मकान में रहने वाला यह परिवार हर रात अनिश्चितता के साये में गुजारता था। बरसात के दिनों में टपकती छत और कमजोर दीवारें एक समस्या थीं, तो दूसरी ओर हाथियों के गांव की ओर आने की खबर पूरे परिवार की नींद उड़ा देती थी। करमचन्द्र बताते हैं कि कई बार पूरी रात जागकर परिवार की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती थी। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य था। इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आई।

मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में नवनिर्मित डोम व किचन शेड का लोकार्पण

जिला खनिज न्यास मद से 75 लाख रूपये की लागत से कालेज में बनाया गया है भव्य डोम एवं कैंटीन हेतु किचन शेड

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने कोरबा के मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में नवनिर्मित भव्य डोम एवं किचन शेड का लोकार्पण किया, इस अवसर पर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी सहित निगम के पार्षदगण, महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के पदाधिकारी व सदस्य सहित काफी संख्या में अन्य नागरिकगण उपस्थित थे।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोरबा के घंटाघर स्थित मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में जिला खनिज न्यास मद से 75 लाख रूपये की लागत से भव्य डोम का निर्माण कराया गया है, इसके साथ ही कालेज में कैंटीन की व्यवस्था हेतु किचन शेड भी बनाया गया है। सोमवार को आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजूदेवी राजपूत के द्वारा उक्त नवनिर्मित डोम एवं किचन शेड का विधिवत लोकार्पण किया गया।

प्रधानमंत्री ने दी है डी.एम.एफ की सौगात इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्थानीय स्तर पर विकास हेतु फंड की व्यवस्था किये जाने के मद्देनजर जिलों में जिला खनिज न्यास मद की सौगात देकर देश व प्रदेश में विकास के रास्ते खोल दिये हैं, जिला खनिज न्यास मद से अधिकांश बड़े विकास कार्य स्कूल, छात्रावास, आंगनबाड़ी, सड़क, भवनों के निर्माण सहित अन्य अधोसंरचना संबंधी विकास के कार्य इस मद से कराये जा रहे हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी जिला खनिज न्यास मद से फंड की व्यवस्था हो रही है, उन्होने कहा कि इसी मद से आज इस कालेज में भव्य डोम व किचन शेड का निर्माण हुआ है, डोम की उपलब्धता से कालेज को विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजनों व सभाओं हेतु एक सुविधापूर्ण स्थल उपलब्ध हो चुका है। श्री देवांगन ने आगे कहा कि एक ओर जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयी ने देश में विकास का नया विजन दिया था, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की छबि विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित हुई है।

कालेज को मिली बेहतर सुविधा

इस अवसर पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा के मंदिर इस महाविद्यालय को एक बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है, भव्य डोम व कैटीन हेतु लोकार्पित किया गया है, जिसके लिये मैं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर संजूदेवी राजपूत को धन्यवाद देता हूँ। उन्होने कहा कि उद्योग मंत्री व महापौर के द्वारा सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे बरसों से व्याप्त समस्याएं दूर हो रही हैं।

निगम क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन करोड़ों के विकास कार्य

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत के द्वारा निगम क्षेत्र में प्रतिदिन करोड़ों रूपये के विकास कार्य प्रारंभ कराए जा रहे हैं, विगत कुछ वर्षो से रूके हुए कोरबा के विकास को गति एवं दिशा दे रहे हैं। उन्होने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देशन में प्रदेश सरकार स्वदेशी के लिये कार्य कर रही है तथा आत्मनिर्भर भारत व स्वावलंबन की दिशा में व्यापक रूप से कार्य हो रहे हैं।

भव्य डोम की सौगात हेतु आभार

महाविद्यालय जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष व वार्ड पार्षद वर्षा दिनेश वैष्णव एवं महाविद्यालय की प्राचार्य पपिया चतुर्वेदी ने इस अवसर पर कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर संजूदेवी राजपूत के द्वारा हमारे कालेज को भव्य डोम एवं कैटीन हेतु किचन शेड की आज एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसके लिये हम उन्हें धन्यवाद अर्पित करती हैं। उन्होने कहा कि इस कालेज में 1500 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अध्ययन करने आती हैं, डोम के निर्माण से छात्राओं के विविध कार्यक्रमों, आयोजनों एवं सभा आदि के लिये एक सुविधापूर्ण स्थान उपलब्ध हो चुका है, जिसके लिये हम उनके प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं।

जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही सरकार की प्राथमिकता - राजेश अग्रवाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में संचालित सुशासन तिहार-2026 आम जनता और प्रशासन के बीच विश्वास, संवाद और त्वरित समाधान का सशक्त सेतु बनकर उभर रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिला के अंबिकापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्रा टिकरा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने शामिल होकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हर्रा टिकरा क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली 27 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी वाले इस शिविर में कुल 1,153 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,106 मांग संबंधी तथा 47 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल रहे। इनमें से 22 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर शासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली का परिचय दिया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण हेतु भेजा गया है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके वास्तविक लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में आयोजित सुशासन तिहार शासन की जवाबदेही और जनोन्मुखी कार्यसंस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि प्रशासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या के समाधान से वंचित न रहे। सुशासन तिहार इसी सोच का परिणाम है, जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासन एक मंच पर उपस्थित होकर जनता की मांगों और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रहे हैं। पेंशन, राशन कार्ड, फौती नामांतरण, सीमांकन जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है और प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निराकरण हमारी प्राथमिकता है। मंत्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 69 हजार से अधिक हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और पात्र शेष उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक आवेदन प्रस्तुत कर योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में विद्यालयों के अतिरिक्त भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 59 स्कूलों को चिन्हित किया गया है।

एक मोटर बदली, कई चेहरों पर लौटी मुस्कान भाटपारा में फिर बहा उम्मीदों का जल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे सूरजपुर जिले के दूरस्थ भाटपारा गांव में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समुदाय के परिवारों के लिए पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब गांव में स्थापित सोलर पावर पंप की मोटर अचानक खराब हो गई, तो लोगों की चिंता बढ़ गई। गर्मी के दिनों में पेयजल की व्यवस्था प्रभावित होने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

लेकिन इस बार उनकी परेशानी लंबी नहीं चली। जैसे ही प्रशासन और संबंधित विभाग को समस्या की जानकारी मिली, तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। खराब मोटर को निकालकर नया मोटर पंप स्थापित किया गया और कुछ ही समय में गांव में फिर से पानी की धार बहने लगी।

जब नल से पानी निकलना शुरू हुआ तो ग्रामीणों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी। महिलाओं को दूर-दूर तक पानी की चिंता नहीं रही और बुजुर्गों ने भी संतोष की सांस ली। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन की तत्परता ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं भी अब प्राथमिकता से सुनी और सुलझाई जा रही हैं।

इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार की असुविधा न हो। गांव के पास स्थित हैंडपंप से लगातार पानी की उपलब्धता बनी रही, जिससे लोगों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ा। भाटपारा की यह छोटी-सी घटना एक बड़े संदेश को सामने लाती हैकृविकास केवल योजनाएं बनाने से नहीं।

नील-हरित काई से खेती की लागत घटा रहे किसान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खेती को अधिक टिकाऊ, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बालोद जिले के किसान अब नील-हरित काई (ब्लू ग्रीन एल्गी) जैसे जैव उर्वरक को अपना रहे हैं। इससे न केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो रही है, बल्कि खेती की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आ रही है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि नील-हरित शैवाल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सायनोबैक्टीरिया कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। इसके उपयोग से प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की पूर्ति संभव है, जिससे किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर कम खर्च करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। बालोद जिले के पथराटोला, कारूटोला और फरदडीह गांवों के कई किसान अपने खेतों में छोटे गड्ढे तैयार कर नील-हरित काई का उत्पादन कर रहे हैं। किसान रोपाई और बियासी के समय इसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे धान की फसल को आवश्यक पोषण मिल रहा है।

कृषि विभाग के अनुसार इसके प्रयोग से धान उत्पादन में 8 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना है। विशेष रूप से जलभराव वाले धान क्षेत्रों के लिए उपयोगी यह जैव उर्वरक किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यही कारण है कि जिले में टिकाऊ और कम लागत वाली खेती की नई राह तैयार होती दिखाई दे रही है।

अब सरकारी सेवाएं मोबाइल की स्क्रीन पर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सरकारी कार्यालयों के चक्कर, लंबी कतारें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के अभाव से होने वाली परेशानियां अब धीरे-धीरे अतीत की बात बनती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में सेवा-सेतु केन्द्रों के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों तक सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप में पहुंचाने की पहल ने सुशासन को नई पहचान दी है।

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

अब प्रदेश के नागरिक 441 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त कर रहे हैं।

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहजता है। सेवा-सेतु केन्द्रों में लगाए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही नागरिकों को उपलब्ध सभी सेवाओं की सूची और प्रत्येक सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी मिल जाती है। इससे लोगों का समय बच रहा है और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी कम हो रही है। डिजिटल सुविधा को और व्यापक बनाते हुए राज्य सरकार ने वॉट्सऐप आधारित सेवा प्रणाली भी शुरू की है।

अब नागरिक एक निर्धारित वॉट्सऐप नंबर पर संदेश भेजकर आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, भू-नकल तथा नाम परिवर्तन से संबंधित सेवाओं सहित सैकड़ों शासकीय सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेवा-सेतु केन्द्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। इससे कम शिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक स्थानीय भाषा तथा वॉयस कमांड के माध्यम से भी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल न केवल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती दे रही है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनोन्मुख बना रही है।

चिरायु योजना बनी वरदान

बिलासपुर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत संचालित चिरायु योजना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि समय पर पहचान और उचित उपचार से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को नया जीवन दिया जा सकता है। बिलासपुर जिले के विकासखंड तखतपुर के चिरायु दल ने संवेदनशीलता, तत्परता और समर्पण का परिचय देते हुए छह वर्षीय मासूम टोकेशवर निर्मलकर को नया जीवन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले इस बच्चे का उपचार राज्य के बाहर हैदराबाद में अत्यंत जटिल ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से संभव हो सका। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ी पहल...

अब गांव-गांव पहुंच रही है हैंड हेल्ड एक्स-रे जांच सुविधा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित विशेष टीबी खोज अभियान उल्लेखनीय परिणाम दे रहा है। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे संभावित टीबी मरीजों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित हो रहा है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में संचालित 100 दिवसीय विशेष अभियान इस दिशा में एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों से अब तक 79 विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 6,472 उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें 2,752 पुरुष और 3,720 महिलाएं शामिल हैं।

हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीन के माध्यम से की गई जांच में 2,392 व्यक्तियों में संभावित असामान्यताएं चिन्हित की गईं, जिनकी आगे ट्रूनॉट जांच के जरिए पुष्टि कर उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस पहल से न केवल टीबी रोगियों की समय पर पहचान हो रही है, बल्कि संक्रमण के प्रसार को रोकने में भी मदद मिल रही है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दो सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बलगम के साथ खांसी, खून आना, सीने में दर्द, लगातार बुखार, वजन कम होना या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और नियमित उपचार से टीबी का पूर्ण इलाज संभव है।

विश्व क्षय दिवस 24 मार्च 2026 से शुरू किए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है। इसके तहत गांव-गांव स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच, जागरूकता और उपचार की व्यवस्था की जा रही है। आधुनिक तकनीक, सक्रिय स्वास्थ्य अमले और जनसहभागिता के बल पर छत्तीसगढ़ टीबी मुक्त राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने वाली यह पहल राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था का सशक्त उदाहरण बन रही है।

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

12 किलो गांजा और 62 पौआ शराब जब्तः नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अवैध कब्जों पर भी चला बुलडोजर

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में दुर्ग पुलिस ने बुधवार को नशे और अवैध गतिविधियों के खिलाफअभियान चलाया। पुलिस ने देवार पारा बस्ती में सघन चेकिंग और तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में गांजा, शराब और धारदार हथियार बरामद किए। कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर छिपाकर रखे गए सामान को जब्त किया गया।

दरअसल, पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि देवार पारा बस्ती में अवैध रूप से गांजा बेचने का कारोबार संचालित किया जा रहा है। इसके बाद करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम गठित कर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 10 से 12 किलोग्राम गांजा बरामद किया।

साथ ही गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक रैपर के कई पैकेट भी जब्त किए गए। इसके अलावा पुलिस ने 18 पौआ देसी सोले मसाला और 44 पौआ गोल्डन गोवा शराब सहित कुल 62 पौआ अवैध शराब भी बरामद की। अभियान के दौरान कुछ धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं।

अभियान के दौरान पुलिस ने बस्ती के घरों, आसपास के खाली स्थानों और अन्य संदिग्ध जगहों की गहन तलाशी ली।

जांच में पता चला कि कुछ लोग मादक पदार्थ और अन्य अवैध सामान को कबाड़ के बोरों, पुराने, खंडहरनुमा भवनों, मकानों की छतों और टॉयलेट जैसी जगहों पर छिपाकर रखते हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने अलग-अलग समूह बनाकर पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो तलवार समेत अन्य धारदार हथियार भी बरामद किए। वहीं बस्ती में खड़ी बिना नंबर की कुछ संदिग्ध दोपहिया वाहनों को जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इन वाहनों के मालिकों और उनके उपयोग के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

अभियान के दौरान पुलिस ने उन स्थानों पर भी कार्रवाई की, जहां नशे के कारोबार की गतिविधियां संचालित होने की सूचना थी। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। पुलिस का कहना है कि बरामद गांजा और शराब किसने लाकर छिपाई थी और इसका उपयोग और बिक्री कौन कर रहा था, इसकी जांच की जा रही है। गांजा बरामदगी के मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

खास खबर

रायपुर के कारोबारी से 84 लाख की ठगी:शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा का लालच दिया

रायपुर। राजधानी रायपुर में शेयर मार्केट और आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) में भारी मुनाफा दिलाने का लालच देकर ठगों ने कारोबारी और उसके परिचितों से 84 लाख 63 हजार रुपए की ठगी की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार सेक्टर-1 देवेंद्र नगर निवासी अविनाश लोखंडे शेयर बाजार से जुड़ी एक ब्रोकिंग फर्म का संचालन करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि जून 2025 में कुछ लोगों ने व्हाट्सऐप के जरिए से उनसे संपर्क किया था। आरोपियों ने खुद को निवेश सलाहकार बताते हुए शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ में कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का दावा किया। उनके झांसे में आकर अविनाश और उनके परिचितों ने अलग-अलग किश्तों में 84 लाख 63 हजार रुपए निवेश कर दिए। बाद में जब मुनाफा और मूल रकम वापस नहीं मिली, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित के अनुसार, शुरुआत में आरोपियों ने अविनाश से एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खाता खुलवाया। कुछ समय तक सामान्य ट्रेडिंग कराकर उन्हें मुनाफा भी दिखाया गया, जिससे उनका भरोसा बढ़ गया।

सूने मकान में लाखों के जेवरात चोरी का खुलासा, भखारा पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा

धमतरी। जिले के ग्राम कोसमर्रा में सूने मकान में हुई चोरी की वारदात का भखारा पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के जेवरात, 10 ग्राम सोने का बिस्किट और वारदात में प्रयुक्त कुदाली बरामद की है। पुलिस के अनुसार, ग्राम कोसमर्रा निवासी कृष्ण कुमार कोसरे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 मई 2026 को वह अपने परिवार के साथ अभनपुर गए हुए थे। 17 मई को लौटने पर घर का मुख्य दरवाजा और आलमारी का ताला टूटा मिला तथा घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी हो चुकी थी। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 50 हजार 700 रुपये बताई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में थाना भखारा और साइबर टीम ने संयुक्त जांच शुरू की। जांच के दौरान संदेही घनश्याम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने साथी हेमंत उर्फ सोनू मानिकपुरी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सूने मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और आलमारी से जेवरात व नगदी चोरी कर ली।

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मौत

रायपुर। भीषण गर्मी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लेकिन मौसम में आए इस बदलाव के साथ आकाशीय बिजली की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान तीन महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा, बीजापुर और मनेंद्रगढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर महिलाएं काम के दौरान बिजली गिरने की चपेट में आ गईं। हादसों में तीन महिलाओं की जान चली गई, जबकि दंतेवाड़ा जिले में 12 ग्रामीण आकाशीय बिजली की चपेट में आने से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने 4 जून से प्रदेशभर में गरज-चमक के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हालांकि अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं।

दुर्ग में कर्मचारियों की पिटाई से पति की मौतः पत्नी का पक्ष लेने पहुंचे 2 कर्मचारी ने लाठी-डंडों से पीटा, दोनों गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग में फार्म हाउस में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने वहां काम करने वाले दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ था, लेकिन पत्नी का पक्ष लेते हुए बाकी कर्मचारियों ने पति की इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई।

मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र ग्राम मोहंदी स्थित खाननाडी के फार्म हाउस का है। यहां सावित्री साहू पिछले करीब सात सालों से काम कर रही थी और वहीं रहती थी। कुछ समय पहले पति नीलकंठ साहू भी उसके साथ रहने लगा था। आसपास के लोगों के अनुसार दंपती के बीच अक्सर विवाद होता था।

बताया जा रहा है कि नीलकंठ अपनी पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। 1 जून की रात करीब 9 बजे नीलकंठ साहू और उसकी पत्नी सावित्री के बीच फिर विवाद हो गया। विवाद के दौरान नीलकंठ ने पत्नी के साथ मारपीट की।

मारपीट में पत्नी के सिर में चोट लग गई। पत्नी के साथ हो रही मारपीट देखकर वहां मौजूद फार्म हाउस के कर्मचारी राजेश वर्मा (50) और अमर सिंह (45) आक्रोशित हो गए। आरोप है कि दोनों ने नीलकंठ की पिटाई शुरू कर दी। राजेश वर्मा ने डंडे से हमला किया।

जबकि अमर सिंह ने हाथ-मुक्कों से लगातार मारपीट की। गंभीर चोटें लगने के कारण नीलकंठ की तबीयत बिगड़ गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पत्नी सावित्री ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

अवैध खनन पर प्रशासन का एक्शन, 7 हाईवा जब्त

रायपुर। रायपुर में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने पटेवा-नवापारा क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध परिवहन में लगे 7 हाईवा वाहनों को जब्त किया। उप-संचालक खनिज राजेश मालवे के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 5 हाईवा रेत और 1 हाईवा गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए गए। विभागीय टीम ने सभी वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया। जब्त वाहनों को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना गोबरा-नवापारा में रखा गया है। जांच अभियान के दौरान एक हाईवा मुरूम का अवैध परिवहन करते भी पकड़ा गया। इस वाहन को जब्त कर उपरवारा थाने में रखा गया है। इस तरह खनिज विभाग ने कुल 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज परिवहन पर सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि, जिले में खनिज विभाग को नियमित औचक निरीक्षण और सघन गश्त जारी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जा सके।

समाधान सेल की सूचना पर कसडोल पुलिस की कार्रवाई, 4 जुआरी गिरफ्तार

बलौदाबाजार-भाटापारा। जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में समाधान सेल की सूचना पर पुलिस ने जुआ खेलने वाले चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नगदी राशि और ताश की गड्डी जब्त की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में आम नागरिकों की शिकायतों और आपराधिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने के लिए संचालित समाधान सेल को जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में कसडोल पुलिस ने कलार पारा स्थित पीपल चौक में घेराबंदी कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान महेश राम जयसवाल (62), रामेश्वर राव (35), बालमुकुंद केवट (55) और राजकुमार केवट (40) को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,270 रुपये नगद और 52 पत्ती ताश की गड्डी जब्त की है। चारों आरोपियों के खिलाफथाना कसडोल में धारा 13 जुआ एक्ट एवं छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाने वाला गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने एक ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की गई है। मामला एक नाबालिग युवती की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसकी जांच के दौरान गंभीर तथ्य सामने आए हैं।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी करीब दो-तीन महीने पहले कॉल सेंटर में काम करने के लिए टेडेसरा आई थी। शुरुआत में वह टेडेसरा स्थित रंजीत सिंह के ढाबे में रहती थी। बाद में वह पिछले 15 दिनों से किराए के मकान में रहने लगी थी। शिकायत में बताया गया है कि पीड़िता ने

अपनी मां को बताया था कि ढाबा संचालक रंजीत सिंह उसके साथ लगातार मारपीट करता था और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। जब भी वह घर लौटने की बात करती थी, आरोपी उसे कमरे में बंद कर देता था और प्रताड़ित करता था। परिजनों के अनुसार, लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर नाबालिग ने आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक दिलीप पटेल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह (22) को हिरासत में लिया। आरोपी मूल रूप से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के ग्राम सौन्दर का निवासी है और टेडेसरा स्थित पीएनआर ढाबा संचालित करता था। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सोमनी पुलिस ने क्षेत्र में शांति भंग करने और विवाद उत्पन्न करने वाले एक अन्य व्यक्ति के खिलाफभी प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

रायगढ़ में पत्थरबाजी कर ट्रक ड्राइवरों से मोबाइल लूटः 5 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों से लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरोह ट्रकों पर पत्थरबाजी कर उन्हें रोकता था और फिर ड्राइवरों से मोबाइल और कैदी लूटकर फरार हो जाता था। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। दरअसल, पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक वाहनों पर पत्थरबाजी कर उन्हें रोकते हैं और ड्राइवरों के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच उर्दना के रहने वाले ड्राइवर ने रोहित कुमार पासवान (18) रिपोर्ट दर्ज कराई।

उसने बताया कि वह मंगलवार रात करीब 1 से 2 बजे के बीच आमाघाट क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी सड़क पर मौजूद कुछ युवकों ने उसके ट्रक पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर लगने से ट्रक का शीशा टूट गया और चालक के सिर में चोट आ गई।

रोहित ने जैसे ही वाहन रोका, एक युवक ट्रक के केबिन में चढ़ गया और उसकी जेब में रखा रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफकेस दर्ज कर मामले को जांच में लिया। पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि ग्राम देलारी का रहने वाला

रघुनाथ चौहान (25) अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ग्राम देलारी में घेराबंदी कर रघुनाथ चौहान और उसके साथी शिव कुमार अघरिया (24) को पकड़ा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों प्रवीण राठिया (21), जय किशन सोनार (19) और किशन कंवर (27) के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

पुलिस ने शिव कुमार के पास से ट्रक चालकों से लूटे गए 6 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें ट्रक चालक रोहित का मोबाइल भी शामिल था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। पूछताछ में सभी आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। मामले में आरोपियों की पहचान परेड अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा के समक्ष कराई गई, जिसमें पीड़ित रोहित कुमार ने सभी आरोपियों की पहचान की। जांच में यह तथ्य सामने आने पर कि पांच आरोपियों ने मिलकर मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था।

मामले में धारा 309(6) को विलोपित कर धारा 310(2) (डकैती) जोड़ी गई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि लूटपाट और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफकार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

दहशत फैलाने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

बिलासपुर। कॉलेज और मंदिर के आसपास लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे एक युवक का आतंक सरकंडा पुलिस ने मिनटों में खत्म कर दिया। हाथ में धारदार बटनदार चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहे आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध धारदार चाकू बरामद किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामला थाना सरकंडा क्षेत्र के अशोक नगर स्थित छ्रस्र कॉलेज और हनुमान मंदिर के आसपास का है। पुलिस को 3 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक हाथ में बटनदार चाकू लेकर खुलेआम घूम रहा है और आने-जाने वाले लोगों को भयभीत कर क्षेत्र में आतंक का माहौल बना रहा है।

खास खबर

सुशासन तिहार में बम्लेश्वरी समूह को मिली छह लाख की सौगात

खैरागढ़। सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में आयोजित समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में खैरागढ़ जिले के ग्राम गोपालपुर के 10 सदस्यीय जय मां बम्लेश्वरी स्व-सहायता समूह को आजीविका संवर्धन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 6 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। समूह की महिलाओं ने बताया कि प्राप्त राशि का उपयोग आजीविका गतिविधियों के विस्तार तथा आय बढ़ाने के लिए किया जाएगा। समूह की सदस्यों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

बिहान योजना : लखपति दीदी रत्ना बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

रायपुर। मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास से सब कुछ हासिल किया जा सकता इसकी मिसाल पेश की है बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड के ग्राम टिकरा धनोरा की रत्ना ठाकुर ने। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर लखपति दीदी बनी रत्ना न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुईं, बल्कि अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। रत्ना ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर के माध्यम से मुर्गीपालन के लिए दाना तैयार कर रही हैं। उनके दाने की मांग स्थानीय कुक्कुटपालकों के अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों तक है। रत्ना ने बताया कि दाना निर्माण के साथ-साथ वह ब्रूडिंग चूजों का पालन-पोषण कर उन्हें बड़ा करती हैं और बाद में होटल एवं ढाबों में उनकी आपूर्ति करती हैं। इस व्यवसाय ने उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रत्ना ने कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। करीब दो एकड़ भूमि पर मल्चिंग विधि से साग-सब्जियों की खेती कर वह हर माह 15 से 20 हजार रुपये तक कीह अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं।

5 नए सरकारी मेडिकल कालेजों में 149 प्राध्यापकों की संविदा भर्ती, 15 तक करें आवेदन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के पांच नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन से प्राप्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में, 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों—दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी (जशपुर), जांजगीर-चांपा और कबीरधाम—में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजीडेंट के कुल 149 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https//monitoringcell.cgdme.in/mpas पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

पदों का विवरण

एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायो-केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन आदि के लिए संविदा पदों का वर्गीकरण किया गया है:-

प्राध्यापक: 35 पद, सह-प्राध्यापक : 40 पद, सहायक प्राध्यापक : 50 पद तथा सीनियर रेजीडेंट : 24 पदों के लिए विज्ञापन निकला गया है।

चयन प्रक्रिया और पात्रता शर्तें

आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव और शोध कार्य राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रचलित मानदंडों और 'मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस, 2025' के अनुरूप होना अनिवार्य है। इसके अलावा, किसी भी राष्ट्रीय या राज्य चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीकरण होना आवश्यक है।

'मुख्यमंत्री किसान संवाद' कार्यक्रम में किसानों से रूबरू हुए सीएम

सिर्फ आजीविका ही नहीं खेती-किसानी हमारी संस्कृति-सभ्यता का भी आधार : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित 'मुख्यमंत्री किसान संवाद' में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है।

कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया।

किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद और उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों ने अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, मौसंबी, पपीता और आम जैसी फसलों की उन्नत खेती के अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का युवा खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में देख रहा है। यह परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक है। राज्य सरकार कृषि आधारित कौशल विकास, ड्रोन संचालन, कृषि मशीनरी, जैविक खेती और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है।

राज्यपाल ने रेत के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खनन को जरूरी बताया

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की नदियों और बड़े नालों में रेत खनन की गतिविधियों को वैज्ञानिक, संतुलित और व्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसके उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इनके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण और जल संसाधनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।

राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से इस विषय पर चर्चा की और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। रेत खनन निर्धारित नियमों एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों उद्देश्यों को समान रूप से साधा जा सके। राज्यपाल ने ड्रोन आधारित निगरानी और खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जानकारी लेते हुए इसकी सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि नदियों और बड़े नालों की प्राकृतिक संरचना तथा जलधारण क्षमता को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अनियोजित खनन गतिविधियों से नदी तटों, भू-जल स्तर और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए खनन कार्यों की नियमित निगरानी और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नदियों एवं जलस्रोतों की क्षमता बढ़ाने तथा भू-जल संरक्षण के लिए दीर्घकालिक और समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। रेत खनन से संबंधित क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। आवश्यकता पड़ने पर आईआईटी जैसे विशेषज्ञ संस्थानों से सर्वे और तकनीकी अध्ययन कराया जा सकता है।

सड़क दुर्घटना में टूट गई श्रोणि (पेल्विस) सिम्स के डाक्टरों ने की सफल जटिल सर्जरी

- उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं, टीमवर्क और विशेषज्ञता का उत्कृष्ट उदाहरण: स्वास्थ्य मंत्री

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं में पेल्विस (श्रोणि) की हड्डी का गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाना तथा साथ ही एसीटैबुलम का फ्रैक्चर होना अत्यंत गंभीर एवं जटिल चोटों में गिना जाता है। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ उपचार न मिलने पर स्थायी विकलांगता, चलने-फिरने में गंभीर कठिनाई तथा भविष्य में गठिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार के एक चुनौतीपूर्ण मामले में सिम्स बिलासपुर के अस्थि रोग विभाग ने सफल सर्जरी कर 40 वर्षीय अजय पटेल को नया जीवन प्रदान किया।

बिलासपुर निवासी अजय पटेल को 19 अप्रैल 2026 को बिल्हा क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें उपचार हेतु सिम्स बिलासपुर लाया गया, जहां उनकी दाहिनी पेल्विस में सेंट्रल हिप डिसलोकेशन के साथ एसीटैबुलम फ्रैक्चर पाया गया।

वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण सिंह ठाकुर की देखरेख में मरीज का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. बेन के मार्गदर्शन में विशेष सर्जिकल योजना तैयार की गई।

28 अप्रैल को ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद राइट एसीटैबुलर रिपेयर एवं ओपन रिडक्शन ऑफ हिप जॉइंट की जटिल सर्जरी की गई। आधुनिक सी-आर्म फ्लोरोस्कोपी मशीन की सहायता से हड्डियों की स्थिति का लगातार मूल्यांकन किया गया, जिससे फ्रैक्चर के टुकड़ों को शारीरिक संरचना के अनुरूप सटीक रूप से स्थापित किया जा सका। इम्प्लांट की सही स्थिति सुनिश्चित की गई तथा हिप जॉइंट का पूर्ण एनाटॉमिकल रिडक्शन प्राप्त किया गया। टूटे हुए एसीटैबुलम की मरम्मत कर उसे स्थिर किया गया तथा जोड़ को पुनः उसकी सामान्य स्थिति में स्थापित किया गया।

मरीज की रिकवरी संतोषजनक रही। सर्जरी के बाद मरीज को विशेषज्ञ फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया, जिससे वह सामान्य गतिविधियों की ओर अग्रसर हो सका।

इस सफलता पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सिम्स बिलासपुर में आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, सी-आर्म आधारित उन्नत ट्रॉमा सर्जरी एवं अनुभवी चिकित्सकों की संयुक्त कार्यप्रणाली के कारण जटिल से जटिल पेल्विस एवं एसीटैबुलर चोटों का सफल उपचार संभव हो रहा है।

खाद के अवैध भण्डारण पर गोदाम सील और खाद जब्त

रायपुर। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी, अवैध भण्डारण और निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी जिलों में गठित उड़नदस्ता दलों द्वारा लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले में मल्हार और सेन्दरी में बड़ी मात्रा में खाद जब्त कर कानूनी कार्रवाई की गई है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड के मल्हार में अग्रवाल खाद भण्डार की जांच के दौरान यूरिया, एनपीके और एसएसपी उर्वरकों का अवैध भण्डारण पाया गया। टीम ने खाद को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार सेन्दरी स्थित मेसर्स बंसल फर्टिलाइजर में छिपाकर रखी गई खाद को उड़नदस्ता दल ने रात में छापेमार कार्रवाई कर बरामद किया। अवैध भण्डारण की पुष्टि होने पर खाद जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया।

जल संरक्षण का मिलने लगा दोहरा लाभ

मोर गांव-मोर पानी : जल संरक्षण और हरियाली की मिसाल बना कांकेर जिला

श्रीकंचनपथ समाचार

कांकेर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर बस्तर कांकेर जिला पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के कारण विशेष पहचान बना रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और 'मोर गांव, मोर पानी' अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन ने जिले के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

'मोर गांव-मोर पानी' से बदली गांव की तस्वीर

जिले में बीते वर्षों के दौरान शासकीय परिसरों, तालाबों की मेड़ों और प्रमुख सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस वर्ष प्रशासन ने केवल पौधारोपण तक सीमित न रहकर पौधों के संरक्षण और उनकी जीवित रहने की दर बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसका सकारात्मक असर भी दिखाई देने लगा है।

जल संरक्षण के क्षेत्र में कांकेर ने प्रदेश में अलग पहचान बनाई है। 'मोर गांव, मोर पानी' अभियान के तहत जिले में भूजल स्तर सुधारने के लिए 11,495 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें 2,597 आजीविका डबरी का निर्माण शामिल है, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है।

इसके अलावा मिनी परकोलेशन टैंक, चेक डैम, गैबियन संरचना, रिचार्ज पिट, सोक पिट और तालाब गहरीकरण जैसे कार्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता को मजबूत किया है।

इन प्रयासों का लाभ किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों को भी मिल रहा है। निजी भूमि पर निर्मित आजीविका डबरियों के आसपास आम, अमरूद और जामुन जैसे फलदार पौधों के रोपण से महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है। जल संरक्षण और हरियाली को साथ लेकर चल रहा कांकेर जिला आज पर्यावरणीय संतुलन और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का सफल मॉडल बनकर उभर रहा है।

आजीविका को सशक्त बनाने की पहल

मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालकों को दी आधुनिक उपकरणों की सौगात

श्रीकंचनपथ समाचार

कोंडागांव। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों को आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरण एवं सामग्री प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम मालाकोट के कमल सिंह नेताम एवं ग्राम जोबा के नरेंद्र कश्यप को मोटर साइकिल और आइस बॉक्स प्रदान किए। इन संसाधनों के माध्यम से अब दोनों हितग्राही अपनी मछलियों को सुरक्षित तरीके से दूरस्थ बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनके व्यवसाय को नई गति मिलेगी। हितग्राहियों ने बताया कि पहले मछलियों के परिवहन और संरक्षण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आइस बॉक्स उपलब्ध होने से अब मछलियों की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। वहीं मोटर साइकिल मिलने से परिवहन आसान होने के साथ-साथ समय और लागत की भी बचत होगी।

कार्यक्रम में ग्राम बड़ेकनेरा के ललित बघेल एवं रामलाल नेताम को मछली पकड़ने के लिए आधुनिक जाल वितरित किए गए। हितग्राहियों ने बताया कि नए जाल मिलने से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित एवं लाभकारी बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक व्यवसायों को आधुनिक संसाधनों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मत्स्य पालन आज ग्रामीण क्षेत्रों में आय का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रहा है और सरकार इस क्षेत्र से जुड़े हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय और जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है।

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मत्स्य पालन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन से प्राप्त यह सहयोग उनके व्यवसाय के विस्तार और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक संसाधनों की मदद से वे अपने मत्स्य व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950